जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:29 अंक:283 दिनांक:24-09-2024 मंगलवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम ग्लोबल फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मानव-केंद्रित दृष्टिकोण सर्वप्रथम होनी चाहिए।

लेबनान में 'इलेक्ट्रॉनिक्स' धमाकों के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात हैं. एक तरफ हिजबुल्लाह के लोग इजराइल के कई शहरों में मिसाइल हमले कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में लोगों की हत्या भी कर रहा है.

जब हम ग्लोबल फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मानव-केंद्रित दृष्टिकोण सर्वप्रथम होनी चाहिए - प्रधानमंत्री

संयुक्त राष्ट्र (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम ग्लोबल फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मानव-केंद्रित दृष्टिकोण सर्वप्रथम होनी चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति के लिए रिफॉर्म की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी मानवता के छठे हिस्से की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं।

पीएम मोदी ने कहा, सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए, हमें मानव कल्याण, भोजन, स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। हमने भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर दिखाया है कि सतत विकास सफल हो सकता है। हम सफलता के इस अनुभव को ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं।

यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। वैश्विक शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार महत्वपूर्ण हैं। सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है... एक तरफ वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, वहीं दूसरी तरफ साइबर, मैरिटाइम, स्पेस जैसे संघर्ष के नए मैदान बन रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल खानी चाहिए।

नरेंद्र मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए संतुलित विनियमन की आवश्यकता है। हमें ऐसे वैश्विक डिजिटल शासन की आवश्यकता है जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रहे।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक पुल होनी चाहिए न कि बाधा। उन्होंने आगे कहा कि भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर एक प्रतिबद्धता है। यही प्रतिबद्धता हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे पहल में भी देखाई देता है.

चक्रवाती तूफान से पलटा ट्रॉलर.....8 मछुआरों की मौत

कोलकाता (ईएमएस)। बंगाल की खाड़ी मेंआए चक्रवाती तूफान के दौरान एक ट्रॉलर पलटने से उसमें सवार 9 मछुआरे फंस गए थे। इसमें से 8 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि एक मछुआरा अभी भी लापता है। यह दुर्घटना एफबी गोविंदो नामक ट्रॉलर की है, इसमें 17 मछुआरे सवार थे। ये सभी हिल्सा मछली पकड़ने के लिए निकलेथे,लेकिन सुंदरबन के बाघेर चार के पास ट्रॉलर अचानक डूब गया।

एक विशाल लहर ने ट्रॉलर के डेक पर मौजूद 8 मछुआरों को समुद्र में बहा दिया। तीन घंटे बाद, एक अन्य ट्रॉलर के मछुआरों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। बचाए गए मछुआरों ने घटना की जानकारी दी। तटरक्षक बल और स्थानीय मछुआरा संगठन की मदद से रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे ट्रॉलर को किनारे लाया गया। मृतकों की उम्र 27 से 55 वर्ष के बीच थी, जिनमें से अधिकांश काकद्वीप के निवासी थे।

भरत ने खड़ाऊं रख सिंहासन संभाला, मैं दिल्ली संभालूंगी-आतिशी

नई दिल्ली,(ईएमएस)। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया है। आतिशी ने करीब 12 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच कर तमाम औपचारिकताएं पूरी कीं। इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में एक खाली कुर्सी रख छोड़ी और खुद दूसरी कुर्सी में बैठीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मेरे मन में भरत की व्यथा है, जिस प्रकार भरत जी ने भगवान श्री राम की खड़ाऊं रखकर अयोध्या का शासन संभाला था, उसी तरह मैं दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। भाजपा ने इसे जनता का अपमान बताया है।

सीएम का पदभार संभालने के साथ ही दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने कहा, कि यह खाली कुर्सी उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए छोड़ रखी है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को एक बार फिर से इसी कुर्सी पर बिठाएंगे। तब तक यह खाली कुर्सी इसी कमरे में रखी रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। आतिशी ने आगे कहा, कि मेरे मन में आज वही व्यथा है जो भगवान श्री राम के 14 साल के लिए वनवास जाते समय भरत जी के मन थी। जिस प्रकार भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊं रखकर अयोध्या का शासन संभाला। उसी तरह से मैं भी आने वाले 4 महीने दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में भाजपा ने कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब तक दिल्ली वाले उनकी ईमानदारी साबित नहीं कर देते, तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और इसी के साथ उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के लोग ही दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिराजमान करेंगे।

केजरीवाल ने जेल से रिहा होते ही दिया था इस्तीफा

दिल्ली की कथित शराब नीति मामले में 13 सितंबर को जमानत पर रिहा होने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 21 सितंबर को आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया और सोमबार 23 सितंबर को उन्होंने सीएम का पदभार संभाल लिया है।

भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साधा और कहा, कि उन्हें अपनी कुर्सी के बगल में खाली कुर्सी नहीं रखना चाहिए था। उन्होंने ऐसा करके मुख्यमंत्री पद की गरिमा और दिल्ली की जनता का अपमान किया है। दिल्ली भाजपा चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, कि ऐसा करके आतिशी ने पद की गरिमा और दिल्ली की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि यह आदर्श पालन नहीं, बल्कि चमचागीरी है। भाजपा के इस बयान के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है।

बुलडोजर से गलत कार्रवाई पर दोषी अधिकारियों से होगी नुकसानी की वसूली

नई दिल्ली (ईएमएस)। बुलडोजर द्वारा त्वरित न्याय करने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन जारी करने की बात कही थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी मांगे थे। 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसके पहले कई महत्वपूर्ण सुझाव सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए हैं।

बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर की कार्रवाई को गैरकानूनी घोषित किया जाना। इस तरह की करवाई जिस अधिकारी के निर्देश पर हुई है। उसको जवाबदेह बनाना और उनसे नुकसानी की वसूली करने के प्रावधान से अवैध कार्रवाई को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को जो सुझाव भेजे गए हैं उनमें अवैध निर्माण को गिराए जाने के पहले किराएदार या मकान मालिक को वेध तरीके से नोटिस सर्विस करने का सुझाव दिया गया है। नोटिस सर्विस के लिए पुख्ता सबूत और गवाह की आवश्यकता को भी जरूरी हो। नोटिस का जवाब देने के लिए न्यूनतम एक माह का समय दिए जाने का सुझाव दिया गया है।

प्राधिकरण अथवा नगरी निकाय संबंधित पक्ष के सभी दस्तावेजों की गंभीरता के साथ जांच करें। दस्तावेजों का उल्लेख फाइल में जाँचकर्ता अधिकारी करें। बुलडोजर से किसी भी संपत्ति को गिराए जाने के पूर्व उसकी कानूनी स्थिति को लेकर भेदभावपूर्ण कार्यवाही नहीं होना। यह जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की सुनिश्चित की जाए।

जिस आधार पर बुलडोजर से संपत्ति गिराई जा रही है। उसके आसपास और कोई ऐसी संपत्ति तो नहीं है। जिसका वही आधार बनता हो। न्याया लय के अवकाश के दिन बुलडोजर की कार्यवाही को बंद रखे जाने का नियम हो। बिल्डिंग बायलाज के हिसाब से यदि निर्माण अवैध है, या नियमों का कुछ हद तक उल्लंघन हुआ है। ऐसी स्थिति में नियम के विपरीत जो निर्माण किया गया है। उसी हिस्से को तोड़ने का प्रावधान हो।

1 महीने की समयावधि खत्म होने के बाद उस संपत्ति पर रहने वाले लोगों को सामान बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय देने का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह के महत्वपूर्ण सुझाव सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए हैं।

30 सितंबर तक बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसा माना जा रहा है, 1 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर से संपत्ति को गिराए जाने के बारे में स्पष्ट गाइडलाइन जारी करेगी। भविष्य में किसी की भी संपत्ति, आरोपों के आधार पर अथवा धार्मिक एवं भेदभाव तरीके से ना गिराई जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए गए हैं।

एनकाउंटर पर हो रही सियासत के बीच यूपी पुलिस ने रखे जातिगत आंकड़े

लखनऊ(ईएमएस)। सुल्तानपुर डकैती के बाद अपराधियों के हुए एनकाउंटर पर खूब राजनीति हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर राज्य की योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स तक कह दिया। वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने इस लूटकांड से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए, जिससे अखिलेश यादव के आरोपों पर सफाई देने की कोशिश की गई। इसके अलावा, एनकाउंटर के आंकड़े भी जारी किए गए, जिनमें बताया गया कि अब तक 208 एनकाउंटर में अपराधियों की मौत हुई है, जिसमें विभिन्न जातियों के अपराधी शामिल हैं। इसमें 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर और 16 यादव जाति के अपराधी ढेर हुए हैं। मार्च 2017 से अब तक यूपी एसटीएफ ने 50 से अधिक माफिया और शातिर अपराधियों को मुठभेड़ में मारा है, और 7000 से ज्यादा इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही, एसटीएफ ने सैकड़ों साइबर अपराधियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वालों को भी गिरफ्तार किया है, जिससे योगी सरकार की कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिशें स्पष्ट होती हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन एनकाउंटर्स पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एसटीएफ द्वारा यादव जाति के अपराधियों के एनकाउंटर पर जातिवादी पक्षपात का आरोप लगाया, खासकर मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद। उन्होंने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा, जिससे विवाद और बढ़ गया। हालांकि, यूपी एटीएस ने लूटकांड के तीसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर कर दिया, जिससे योगी सरकार ने अखिलेश यादव के आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश की। पुलिस ने यह संदेश दिया कि सरकार की कानून व्यवस्था जाति पर आधारित नहीं है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर केंद्रित है।

भारत में मंकीपॉक्स के घातक स्ट्रेन की एंट्री से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, नए दिशानिर्देश जारी

तिरुवनंतपुरम। अफ्रीका में एमपॉक्स जमकर तबाही मचा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। वहीं, अब भारत में एमपॉक्स का नया स्ट्रेन मिलने से चिंता पैदा कर दी हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि मलप्पुरम जिले के 38 वर्षीय व्यक्ति में क्लेड 1बी स्ट्रेन पाया गया हैवहीं अब केरल सरकार ने नए सिरे से एमपॉक्स को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

वहीं, अब केरल सरकार ने नए सिरे से एमपॉक्स को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। सूत्रों ने बताया कि मरीज की हालत स्थिर है।

उन्होंने कहा कि 'यह मौजूदा स्ट्रेन का पहला मामला है, जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले महीने एमपॉक्स को दूसरी बार सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। अफ्रीका महाद्वीप में तबाही मचाने वाले मंकीपॉक्स वायरस का खतरनाक वेरिएंट, क्लेड-1 अब भारत पहुंच गया है। देश में इस घातक वायरस का पहला मामला केरल में सामने आया है।

लोकपाल ने कहा विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत करें, अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को

नई दिल्ली (ईएमएस)। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के खिलाफ लोकपाल में दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कराई गई है। लोकपाल और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एएम खानविलकर ने शिकायत कर्ताओं से कहा है। वह भ्रष्टाचार के संबंध में पर्याप्त विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

लोकपाल ने प्रथम सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं द्वारा हिडनबर्ग की रिपोर्ट को डाउनलोड कर जल्दबाजी में शिकायत में संलग्न करने की बात कही है। लोकपाल ने कहा है, शिकायत कर्ता 3 सप्ताह के अंदर हल फनामा दाखिल करें। शिकायत कर्ता यह भी बताएं कि श्रीमती माधवी पुरी के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के दायरे में यह शिकायत किस तरह से आती है। अब इस मामले की सुनवाई लोकपाल17अक्टूबरको करेंगे।

जितने भी तेल और घी बिक रहे उनकी जांच हो- राम मंदिर के मुख्य पुजारी

अयोध्या (ईएमएस)। पूरे देश में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिले मांस और चर्बी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक ओर जहां साधु संत नाराज हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी जांच की मांग हो रही है। अब अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि देश में जितने भी तेल और घी बिक रहे हैं, उन सभी की जांच होनी चाहिए।

राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य दास ने कहा, हमारे मठ मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा है। हम देश के सभी मठ मंदिरों से अपील कर रहे हैं कि मठ मंदिरों में जो भी भोग लगाया जाए, वह मठ मंदिर के कर्मचारियों से ही प्रसाद को तैयार कराएं। उसके बाद भोग लगाए। इतना ही नहीं बाजार में जितने भी तेल और घी बिक रहे हैं,

बाप रे बाप मधुमक्खियों के डंक से चार लोगों की मौत

रांची (ईएमएस)। झारखंड की राजधानी रांची के तुपुदाना में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां मधुमक्खियों के डंक से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हुई है। मृतकों में एक महिला, उसकी दो बेटियां और परिवार का एक और बच्चा शामिल है। महिला खूंटी जिले के कर्रा ब्लॉक के कोसंबी गांव की रहने वाली थी।

पीड़िता के पति सुनील बारला ने बताया कि उसकी पत्नी ज्योति अपनी दो बेटियों के साथ अपने मायके गई थी। वहां पर अपने सभी बच्चों और गांव के कुछ लोगों के साथ नहाने के लिए कुएं पर गई थी और मधुमक्खियों के झुंड में फंस गई। जानकारी के मुताबिक, अचानक मधुमक्खियों का झुंड कुएं के पास पहुंचा और बच्चों को काटने लगा। मधुमक्खियों के झुंड को देखकर सभी भागने लगे लेकिन गांव कुएं से काफी ऊंचाई पर था। देखते ही देखते मधुमक्खियों ने 4 लोगों अपना शिकार बना लिया।

बदलापुर यौन उत्पीड़न केस के आरोपी का नाटकीय एनकाउंटर !

ठाणे (ईएमएस)। बदलापुर यौन उत्पीड़न केस के आरोपी ने पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीन पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले महीने एक पुरुष सहायक द्वारा स्कूल के शौचालय में चार साल और पांच साल की दो बच्चियों का यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला सामने आया था। इसी पुरुष सहायक अक्षय शिंदे की मौत हुई है।

पुलिस ने बताया कि अक्षय शिंदे ने पुलिस की गाड़ी में पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी, आरोपी ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। शाम 5:30 बजे तलोजा जेल से क्राइम ब्रांच बदलापुर ले जाते समय करीब साढ़े छह बजे आरोपी ने यह वारदात की। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की पुष्टि ठाणे पुलिस कमिश्नर ने भी की है।

योगी शासन में खूंखार अपराधियों के एनकाउंटर का अर्धशतक पूरा

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साढ़े सात वर्ष के कार्यकाल में यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने खूंखार अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराने में अर्धशतक लगा लिया है। 50वें अपराधी के रूप में एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी बदमाश अनुज को मार गिराया। सोमवार सुबह सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल एक लाख के इनामी अनुज को एसटीएफ ने उन्नाव में एनकाउंटर में ढेर किया था। एसटीएफ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एसटीएफ ने विभिन्न आपराधिक मामलों में लिप्त 872 अपराधियों व अवैध नशा तथा हथियार तस्करों सहित 379 साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। वहीं 7,015 कुख्यात और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसटीएफ की ओर से लगातार काम हो रहा है। एसटीएफ की सक्रियता से पिछले साढ़े सात वर्षों में 559 से अधिक आपराधिक घटनाओं को घटित होने से पहले रोका गया। इसमें जनप्रतिनिधि, प्रतिष्ठित व्यक्ति, आम नागरिकों के अपहरण, लूट, हत्या जैसे अपराध की घटनाएं शामिल हैं। साथ ही 3,970 संगठित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यश ने बताया कि एसटीएफ ने परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी धांधली को रोकने एवं जड़ से खत्म करने के लिए 193 गिरोहों के 926 सरगना और साल्वरों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं अभियान चलाकर अवैध हथियारों के 189 तस्करों की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से 2,080 अवैध शस्त्र और 8,229 अवैध कारतूस बरामद किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अवैध नशे के कारोबार में लिप्त 1,082 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 91 147.48 किलो गांजा, 2054.651 किलो चरस, 19727.1 किलो डोडा, 7.06 किलो मारफीन, 723.758 किलो स्मैक, 21.521 किलो हेरोइन, 181.012 किलो अफीम व 6.1 किलो ब्राउन शुगर बरामद की गई। इसप्रकार प्रतिबंधित वन्य जीवों का शिकार कर उनकी तस्करी करने वाले विभिन्न गिरोह के 170 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 341 किलो कछुआ कैलीपी, 2 पैंगोलिन, एक बाघ की खाल, 18 किलो बाघ की हड्डी, दो हाथी दांत, 8011 कछुए, 563.1 किलो लाल चंदन की लकड़ी, 44 हाथी दांत से बनी वस्तुएं, तेंदुए के 25 दांत व 24 नाखून व 110 सियार सिंगी तथा अन्य वस्तुएं बरामद की गई हैं।

भाजपा ने हिंदू समाज का वोट लेकर उनके साथ धोखा किया, शंकराचार्य ने भाजपा पर साधा निशाना

गौहत्या और गौमांस निर्यात पर पाबंदी न लगाने का लगाया आरोप

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौहत्या और गौमांस निर्यात के मुद्दे पर भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी ने हिंदुओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि जब तक देश में गौहत्या बंद नहीं होती, वे चुप नहीं बैठेंगे।

लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भाजपा ने बहुसंख्यक हिंदू समाज का वोट तो लिया, लेकिन गौहत्या पर रोक लगाने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तीन बार सत्ता में आने के बावजूद भाजपा ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण उन्हें मठ से निकलकर आंदोलन छेड़ने की जरूरत महसूस हुई।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत अयोध्यासेकीहैऔरअब लखनऊ पहुंच कर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। वह अपने समर्थकों के साथ देशभर का दौरा करेंगे और तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक गौहत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लग जाता।

लापता लेडीज ऑस्कर 2025 में ऑफिशियल एंट्री....क्या पूरा होगा आमिर खान का सपना

मुंबई (ईएमएस)। डायरेक्टर किरण राव की फिल्म लापता लेडीज इस साल मार्च में रिलीज हुई और फिल्म को समीक्षकों के साथ-साथ जनता ने भी बहुत पंसद किया था। समाज में महिलाओं की पहचान को लेकर, मजेदार कॉमेडी के साथ सवाल उठाती ये फिल्म इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है।

फिल्म देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा था कि भारत की ओर से लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए भेजा जाना चाहिए। आखिरकार दर्शकों की ये डिमांड पूरी हो गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की स्लीपर हिट्स में से एक लापता लेडीज भारत की तरफ से इस साल ऑस्कर की आधिकारिक फिल्म होगी। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी ने 29 फिल्मों की एक लिस्ट में से लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए ऑफिशियल एंट्री चुना है। कमेटी के सामने पहुंचीं 29 फिल्मों की लिस्ट में एनिमल और आट्टम जैसी फिल्में भी शामिल थीं। लापता लेडीज की पहली स्क्रीनिंग पिछले साल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुई थी जहां मूवी को जबरदस्त तारीफें मिली थीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 5 करोड़ रुपये से कम बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 25 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया। इस बेहतरीन फिल्म के लिए अभिनेता नितांशी गोयल, प्रतिभा रांटा, स्पर्श श्रीवास्तव, छाया कदम और रवि किशन की भी जमकर तारीफ हुई।

क्या पूरा होगा आमिर का सपना?

लापता लेडीज सुपरस्टार आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म है। उनकी पूर्व पत्नी फिल्ममेकर किरण राव फिल्म की को-प्रोड्यूसर हैं। ये आमिर के प्रोडक्शन में बनी चौथी फिल्म है, जिसे इंडिया की तरफ से ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री बनाया गया है। 2001 में रिलीज हुई लगान आमिर के प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म थी, जिसे भारत की ओर से ऑस्कर में भेजा गया था। इसके बाद उनके प्रोडक्शन में बनीं तारे जमीं पर और पीपली लाइव भी ऑस्कर के लिए भेजी जा चुकी हैं।

जहां लगान ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने में कामयाब हुई थी, वहीं आमिर की प्रोडयूस की हुई बाकी दो फिल्में शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकी थीं। मगर अब चौथी बार आमिर के पास ये मौका आया है कि उनकी फिल्म भारत की ऑफिशियल एंट्री बनकर ऑस्कर की रेस में शामिल हो रही है। अब नजरें इस बात कर रहेंगी कि लापता लेडीज का ऑस्कर में सफर कहां तक पहुंचता है।

लापता लेडीज को भारत के ओर से ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री बनाए जाने पर फिल्म अभिनेता रवि किशन ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये सपना सच होने जैसा मोमेंट है। ये सबसे बड़ा सम्मान है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतनी दूर पहुंच पाऊंगा। ये मेरी जिंदगी की बेस्ट और सबसे बड़ी खबर है।

मायके से 30000 औषधि पौधे लाकर ससुराल में लगाए

-बिना पढ़ी-लिखी विदेशियों को पढ़ा रही है

अनुभव और ज्ञान के आधार पर पाया पद और सम्मान

उदयपुर(ईएमएस)।राजस्थान के उदयपुर जिले के कराकली गांव में रहने वाली 70 साल की प्रतापीबाई एक भी क्लास नहीं पढ़ी है। जब उनकी शादी हुई थी, तो ससुराल से बिना दहेज के आई थी। वह अपने साथ कुछ औषधि पौधे लेकर आई थी। जिसे उसे अपनी ससुराल में लगाया।

अपने दादा और पिता से उसने औषधि पौधों के गुणो के बारे में जाना था। पिछले 60 साल से वह मायके से अपनी ससुराल मे औषधि पौधे लाकर लगा रही है। अभी तक वह 25000से अधिक औषधि पौधे लगा चुकी है।

प्रतापीबाई से जड़ी बूटियां के औषधि गुण सीखने के लिए देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन, हांगकांग, थाइलैंड,जर्मनी मे जाकर वह शिविर लगा चुकी है। राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गेट अलवा ने उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एनजीओ के लिए दी थी। मार्गेट अलवा की असाध्याय बीमारी का उन्होंने इलाज किया था।

देश और विदेशों से बहुत सारे छात्र उनसे विभिन्न पौधों के पत्ते, तने, और छाल के औषधि गुण के बारे में उन्हें जानकारी देती हैं।जो लोग जानकारी लेने के लिए आते हैं। प्रतापीबाई बोलती है, वह वह लिखते हैं। उनसे पूरक प्रश्न भी पूछते हैं।बिना पढ़ी-लिखी होने के बाद भी,जिस तरह से वह एक कुशल वैद्धराज की तरह शिक्षा देती है।उससे स्पष्ट है, अनुभव से ज्ञान आता है। डिग्रियों से ज्ञान नहीं मिलता है।

धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय कॉन्सेप्ट, ये भारतीय अवधारणा नहीं -आरएन रवि के इस बयान पर विवाद

नई दिल्ली (ईएमएस)। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने कथित तौर पर कहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कन्याकुमारी में एक समारोह में कहा , इस देश के लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी हुई है और उनमें से एक ये है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या करने की कोशिश की है।

राज्यपाल ने कहा, धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय कॉन्सेप्ट है। ये भारतीय अवधारणा नहीं है। यूरोप में, धर्मनिरपेक्षता इसलिए आई क्योंकि चर्च और राजा के बीच लड़ाई हुई थी। भारत धर्म से दूर कैसे हो सकता है? धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा है और इसे वहीं रहने दें। भारत में, धर्मनिरपेक्षता की कोई जरूरत नहीं है।

आरएन रवि के इस बयान ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विरुधुनगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद मणिकम टैगोर और सीपीआई नेता वृंदा करात ने राज्यपाल के बयान की आलोचना की है। मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, धर्मनिरपेक्षता पर तमिलनाडु के राज्यपाल का बयान अस्वीकार्य है। ये भारत के संविधान और महात्मा गांधी, बाबासाहेब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के विचार के भी खिलाफ है।

मणिकम टैगोर ने आगे कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल रवि संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। भाजपा और आरएसएस भारत के संविधान को बदलने के पक्ष में हैं, जो बाबा साहेब अंबेडकर की सोच पर आधारित है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल रवि ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं।

तमिलनाडु के राज्यपाल के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की नेता बृंदा करात ने कहा कि राज्यपाल रवि की टिप्पणी हैरान करने वाली है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि संविधान उनके लिए बहुत अधिक मायने नहीं रखता है।

भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर निशाना साधते हुए, सीपीआई नेता ने कहा कि वो उन लोगों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर रही है, जो देश की सर्वोच्च नियम पुस्तिका संविधान में विश्वास नहीं करते हैं।

जन हितैषी

संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का सरकारी शोषण?

पिछले कई दशकों से सरकार खाली पदों को नहीं भर रही है। रिक्त पदों को भरने के स्थान पर स्वीकृत पदों की कटौती कर रही हैं। सेवा निवृत्ति कर्मचारी के स्थान पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में संविदा के आधार पर ठेकेदारी प्रथा पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को रखा जा रहा है। कई सालों से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्हें नियमित नहीं किया गया। उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है। सरकारी कमर्चारियों की तरह उन्हें कोई सुविधा भी नहीं मिलती है। दैनिक वेतन भोगियों और संविदा कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित नहीं है। दो दशक पहले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सरकारी विभागों में रिश्वत देकर नौकरी पाते थे। परिवार वालों को लगता था, एक बार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हो गई। आगे चलकर वह नियमित कर्मचारी हो जाएंगे। दो दशक से ज्यादा हो गए, अभी तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। सरकारें, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय स्तर पर तथा राज्यों के स्तर पर बड़े पैमाने पर संविदा नियुक्ति की जा रही है। सरकारी विभागों में कार्यालयों के काम ठेके पर दिए जा रहे हैं। ठेकेदार संविदा में कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। सरकार जो पैसा कर्मचारियों के लिए ठेकेदार को भुगतान करती है, उससे 30 से 40 फ़ीसदी कम पैसा ठेकेदारों द्वारा संविदा कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। देश भर के सभी राज्यों में लाखों लोग संविदा नियुक्त पर काम कर रहे हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या भी प्रत्येक राज्य में लाखों में है। राज्य सरकारों और नगरीय निकायों और राज्य सरकारों के पद कई वर्षों से खाली पड़े हुए हैं। सरकार उन्हें कर्मचारियों को नियमित करके नहीं भर रही है। कई वर्षों से भर्ती प्रक्रिया भी बंद है। सारी सरकारी सेवाएं गड़बड़ाती चली जा रही हैं। नगरीय निकाय, कलेक्टर कार्यालय, संभागीय कार्यालय, मंत्रालय, संचालनालय, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय सब जगह पर संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसका खामियाजा आम आदमी और सरकार दोनों को ही भुगतना पड़ रहा है। राजस्व विभाग में जमीन के रिकॉर्ड का काम संविदा के कर्मचारी देख रहे हैं। परिवहन विभाग के लाइसेंस संविदा कर्मचारी बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की सुविधा भी संविदा कर्मचारियों के भरोसे है। कंप्यूटर में राजस्व रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी किए जाने के समाचार रोजाना मिल रहे हैं। करोड़ों की जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही है। संविदा कर्मचारियों के माध्यम से सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड को मनमाने तरीके से बदला जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवाएं ठेके पर चल रही हैं। आउटसोर्स में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्हें विभिन्न योग्यता के अनुसार अधिकतम 10000 से 15000 रूपये के बीच प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों से निर्धारित समय के बाद भी काम कराया जा रहा है। उसका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। अधिकारियों द्वारा दैनिक भोगी और संविदा कर्मचारियों का लगातार आर्थिक एवं शारीरिक शोषण किया जा रहा है। उनकी सेवाएं समाप्त करने के नाम पर यह शोषण पिछले कई वर्षों से चल रहा है। सरकार से संविदा कर्मचारियों के लिए 15,000 और 20,000 रूपये प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी को 7,000 से 10,000 रूपये का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाता है। इन सारी गड़बड़ियों के बारे में सरकार और उनके अधिकारियों को पता है। सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों का ठेके में बड़ा कमीशन होता है, जिसके कारण दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स कर्मचारियों का आर्थिक शोषण लगातार हो रहा है। पहले सरकारी विभागों में दैनिक वेतन भोगी के रूप में जो कर्मचारी काम करते थे, इस आधार पर उनकी शादी भी हो जाया करती थी। तब यह माना जाता था, कि कुछ सालों के बाद उक्त कर्मचारी नियमित हो जाएगा। जो कर्मचारी 15-20 साल से लगातार काम कर रहे हैं, आज तक वे नियमित नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की शादी भी नहीं हो पा रही है। उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। 10,000 से 12,000 रूपये महीना उन्हें मिलते हैं। ऐसे में वह कैसे अपना पेट भरेंगे और कैसे परिवार को पाल पाएंगे। आर्थिक कारणों से युवाओं की शादी नहीं होना आम बात हो गई है। युवाओं में अब इस स्थिति में गुस्सा देखने को मिलने लगा है। श्रम न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकारों द्वारा किए जा रहे शोषण पर आंख बंद करके बैठे हैं। ऐसी स्थिति में अब युवाओं का गुस्सा देखने को मिलने लगा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जल्द ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के मामले का कोई हल नहीं निकाला गया तो स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

एक नेशन-एक इलेक्शन, राजनेताओ का टेशन

- जनता जर्नादन के कई सबाल एक नेशन एक इलेक्शन के कितने लाभ और कितने नुकसान

विश्व के विशालत्तम लोकतंत्र भारत के चहूँ दिशाओं में एक ही गरमा गर्म चर्चा व चिन्तन हो रही है। अब यह मुद्दा लोकतंत्र का महापर्व चुनाव तक सीमित ना रह कर राजनीतिक दलों में बहस का मुद्दा बन गया है। विगत दिनों मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद वन नेशन-वन इलेक्शन के लाभ और नुकसान पर गर्मा गर्म बहस छिड़ सी गई है। ऐसे में जनता जर्नादन के कई सबाल एक नेशन एक इलेक्शन के कितने लाभ और कितने नुकसान,मोदी सरकार व सतारूढ़ सहयोगी राजनीतिक दलो के लिए यह मोदी मिशन है,वही कॉंग्रेस समेत 15विपक्षी राजनीतिक दलों व क्षेत्रीय दलों के लिए टेशन है।

आप को बता दे कि एक राष्ट्र-एक चुनाव की नीति के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इस संदर्भ में मोदी सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र यानी नवंबर -दिसंबर में इस बारे में बिल पेश करेगी। सर्व विदित रहे कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने इस पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी ने सिफारिश की थी कि लोकसभा और राज्यों के विधान सभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए। वन नेशन-वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोक सभा और सभी राज्यों के विधान सभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा में कराए जाएं। पी एम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ तीन या चार महीने के लिए होने चाहिए,पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनावों में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न बढ़े। इसके पीछे मोदी सरकार का तर्क है कि इससे जनता को बार-बार के चुनाव से मुक्ति व चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंट में इजाफा होगा। सरकारें बार-बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा,अधिकारियों का समय और एनर्जी बचेगी। इसका बड़ा आर्थिक फायदा भी है। सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। आप के सबाल होगे कि वन नेशन-वन इलेक्शन का सुझाव किसने व कब दिया। आपको बता दे कि केन्द्र सरकार नें विगत दिनों पूर्व वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को कमेटी बनाई गई थी। कोविंद की कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह,पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद,जाने माने वकील हरीश साल्वे,कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी,15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुभाष कश्यप,पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त(ण्न्न) संजय कोठारी समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के विशेष सदस्य बनाए गए हैं। कमेटी ने इसके लिए 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया। इनमें से 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। वहीं,15 दलों ने इसका विरोध किया था। जबकि 15 ऐसी पार्टियां भी थीं,जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 191दिन की रिसर्च के बाद कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी. कमेटी की रिपोर्ट 18 हजार 626 पेज की है। कोविंद समिति के सिफारिशें पर नजर डाल लेते है।

*वन नेशन -वन इलेक्शन की ओर बढ़ने के लिए सरकार को एक बार ही एक बड़ा कदम उठाना होगा।

*इसके तहत केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2029 के बाद एक तारीख तय करेगी।

*इस तारीख पर ही सभी राज्यों की विधानसभाएं भंग हो जाएंगी।

-इसके बाद पहले फेज में लोकसभा के टर्म के हिसाब से सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे।

*इसके 100 दिन के अंदर दूसरे फेज में नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।

*इन सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी।

*लोकतंत्र में कोई सरकार गिर भी सकती है. ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के कारण लोकसभा या किसी विधानसभा के भंग होने पर ये सुझाव दिया गया है कि नए चुनाव उतने ही समय के लिए कराए जाएं, जितना समय सदन का बचा हुआ है।

*इसके बाद लोकसभा के साथ फिर नए सिरे से चुनाव कराए जाएं।

*इस कानून को पास कराने के लिए 18 संवैधानिक संशोधन ज़रूरी होंगे ज़्यादातर संशोधनों में राज्यों की मंज़ूरी जरूरी नहीं है।

*इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले देश भर में जनता और अलग-अलग नागरिक संगठनों की राय ली जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते में सबसे पहले तो संसद में ही चुनौती आएगी। एक देश एक चुनाव के लिए कई संवैधानिक संशोधनों की ज़रूरत होगी। इसके लिए संसद के दोनों ही सदनों में सरकार के सामने दो-तिहाई बहुमत जुटाने की चुनौती है।

*राज्यसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। 245 सीटों में से एन डी ए (ँ्र)को 112 सीटें ही हासिल हैं,जबकि दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 164 पर होगा।

*लोकसभा में भी 543 सीटों में से दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 362 है,जबकि एनडीए (ँ्र)के पास 292 सीटें ही हैं। हालांकि,दो-तिहाई बहुमत का फैसला वोटिंग में हिस्सा लेने वाले सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होता है।

*वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संघवाद की चिंता भी है। कुछ जानकारों का कहना है कि इससे भारत की राजनीतिक व्यवस्था के संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा। राज्य सरकारों की स्वायत्तता कम होगी। विधि आयोग भी मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में एक साथ चुनाव की व्यावहारिकता पर सवाल उठा चुका है।

*व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो एक साथ चुनाव कराने में भारी मात्रा में संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम करना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी मात्रा में ई बी एम(ँ्रे)और ट्रेंड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी.ताकि पूरी चुनावी प्रक्रिया ठीक से पूरी की जा सके।

*वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का भी सवाल है। अक्सर होने वाले चुनावों के ज़रिए जनता समय-समय पर अपनी पसंद तय कर सकती है, लेकिन अगर सिर्फ 5 साल बाद ऐसा होगा,तो जनता की इस पसंद को ज़ाहिर करने में दिक्कत आएगी।

*इससे एक पार्टी के प्रभुत्व का ख़तरा बढ़ जाएगा। कई अध्ययन बताते हैं कि जब भी एक साथ चुनाव होते हैं,तो एक ही पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों में घालमेल हो जाता है।

*वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई कानूनी पेचीदगियां हैं। कई जानकारों का कहना है कि एक देश एक चुनाव के कानून को कई संवैधानिक सिद्धांतों पर भी खरा उतरना पड़ेगा। अगर एक देश,एक चुनाव होता है तो ये चुनाव प्रक्रिया पांच साल में एक ही बार होगी या फिर बीच में कुछ विधानसभाएं भंग हुईं,तो उतनी बार चुनाव होंगे। समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नयी लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। समिति ने कहा कि लोकसभा के लिए जब नये चुनाव होते हैं,तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होगा। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं,तो ऐसी नयी विधानसभाओं का कार्यकाल(अगर जल्दी भंग नहीं हो जाएं)लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल तक रहेगा। समिति ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83(संसद के सदनों की अवधि)और अनुच्छेद172(राज्य विधानमंडलों की अवधि)में संशोधन की आवश्यकता होगी। समिति ने कहा,इस संवैधानिक संशोधन की राज्यों द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसने यह भी सिफारिश की कि भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करे। समिति ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए मतदाता सूची से संबांधित अनुच्छेद 325 को संशोधित किया जा सकता है। आप को बता दें कि वन नेशन-वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में चुनौतियां भी कम नहीं है। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। वैसे तो लोक सभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पाँच साल का होता है लेकिन इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश,एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखें। अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं,जिनकी संख्या सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग-अलग होने से इनकी संख्या पूरी पड़ जाती है। एक साथ लोक सभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इनको पूरा करना भी चुनौती होगी। देश में एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षाबलों की जरूरत को पूरा करना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा।

हम आपको बता दें कि वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग-अलग विचार हैं,इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा,लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं। इनका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन-वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे।

केंद्रीय कैबिनेट ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया है। मोदी सरकार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन एक मिशन है। वन नेशन वन इलेक्शन का बीजेपी(ँ्र,)जेडीयू (व्ळ)ए आई ए डी एम के (ँ्रंश्ख)ए न पी पी(ऱ्प्र,)बी जे डी(ँ्र)अकाली दल,एल जे पी (आर(ध्र्)अपना दल (सोनेलाल)ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन,असम गण परिषद व शिवसेना (शिंदे गुट)ने समर्थन किया है। खास बात ये है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी ँ पर पोस्ट करते वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया है। मायावती ने इसे पार्टी का पॉजिटिव स्टैंड बताया है। वही सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के संग समाजवादी पार्टी (एड्ढ)आम आदमी पार्टी(ँ्र) सीपीएम(ण्ड्श)सी पी आई (ण्ड्ढ)टी एम सी(ऊश्ण)डी एम के (अ्श्ख)ए आई एम आई एम (ँघ्श्घ)व सी पी आई-एम एल (ण्ड्घ-श्थ)समेत15दल इसके खिलाफ है। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा(व्श्श)इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग(घ्ळश्थ)समेत15दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई जवाब नहीं दिया। आपके मन में प्रशन उठना स्वाभाविक है कि क्या वास्तविक मे वन नेशन -वन इलेक्सन लागु हो सकता है तो हम आप को बता दे कि कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव हर 5 साल पर एक साथ होते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव दो साल बाद होते हैं।

*स्वीडन में राष्ट्रीय,प्रांतीय और स्थानीय चुनाव हर चार साल पर एक साथ होते हैं।

*इंग्लैंड में भी संसद कार्यकल निधारित अवधि अधिनियम2011 (इ्ग्-ीर्ऱ ईेर्सिहेंर् ू,2011)के तहत चुनाव का एक निश्चित कार्यक्रम है। वही जर्मनी और जापान की बात करें,तो यहां पहले पीएम का सिलेक्शन होता है,फिर बाकी चुनाव होते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव साथ में होते हैं। अपने देश में आजादी के बाद से 1952,1957,1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे,यानि 1967 तक लोकसभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे,लैकिन विषम परिस्थितियों उत्पन्न होने के कारण इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। क्योंकि संघीय व्यवस्था व राज्यो की स्वायता व आश्यकता को ध्यान में रखकर कर किया गया है। परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ,कालान्तार में क्षेत्रीय दलों नें स्थानीय मुद्दों को उठाया है तथा कई राज्यों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सता से सिंधासन से दुर रखते हुए सरकार बनाई व केन्द्र सरकार बनाने में भी अपनी अंहम भुमिका निभाई है। वही भारतीय राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले राजनीतिक पंडितयों में भी दबी जुबान से चर्चा होने लगी है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार तो किसी तरह बना ली है। लैकिन जनता के मध्य मोदी मैजिक की चमक फीकी हुई उनकी लोक प्रियता में कमी है। जिन के कारण केन्द्र की भाजपा व सहयोगी दलों चिन्ता की लकीरें स्पष्ट नजर आने लगी है। ऐसे मोदी सरकार जनता के समाने चुतराई के चक्र से वन नेशन - वन इलेक्शन च चक्रब्यहु के झाल फैसा कर केन्द्र के संग राज्यों की सता व सिंधासन आसीन हो का दिवा स्वपन्न देख रही है। क्योंकि इनके पास भोली भाली जनता के शँखों में धुल झोकने के लिए कोई मुद्दे नही रह गये है। वही देश की जनता महंगाई,बेरोजगारी त्रस्त है। वैसे भी एक राष्ट्र - एक चुनाव की नाव चुनौतीयों से भरा हुआ है। जिसकी असली पतवार जनता जर्नादन के पास है। जिसकी झलक भारतीय मतदाताओं हाल में ही लोक सभा साधारण चुनाव 24 के दौरान दे कर अबकी 400 पार का सपना चकना चुर कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लागु करना साहिब के लिए इतना आसान नही है। जितना वे समझ रहे,क्योंकि ये पब्लिक है ,पब्लिक साहिब ये सब जानती है। (लेखक- विनोद कुमार सिंह/ ईएमएस)(नोट-लेखक स्वतंत्र पत्रकार व स्तम्भकार है।)

स्वच्छ भारत मिशन ने बदली भारत की छवि

इन दिनों समूचे भारत में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विशेष रूप से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, कार्यालयों, सार्वजनिक व पर्यटक स्थलों, रेलवे स्टेशनों तथा आसपास के परिसरों आदि की साफ – सफाई के लिये विशेष सफाई अभियान चलाकर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है ताकि स्वच्छता अभियान सतत चलता रहे। विगत 19 सितम्बर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उज्जैन प्रवास पर थीं। इस दौरान उन्होंने महाकाल परिसर में झाड़ू लगाकर श्रमदान कर यह संदेश दिया कि चाहे कोई व्यक्ति कितने ही बड़े पद पर क्यों न हो, स्वच्छता उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों की चर्चा करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि इंदौर ने लगातार सात बार देश का स्वछतम शहर बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। राज्य के अनेक शहर वाटर प्लस और ओडीएफ डबल प्लस की श्रेणी में पुरस्कृत हुए हैं। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों का श्रेय अग्रिम पंक्ति के सफाई मित्रों को दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण सन 2025 तक चलेगा। इस दौरान हमें संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को पूरा करना है।

हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भी राजस्थान के झुंझुनू जिला में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश के अधिकांश परिवारों में शौचालयों का नहीं होना एक अभिशाप था। इससे सबसे ज्यादा बेटियों और महिलाओं को शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी लेकिन अब स्वच्छ भारत मिशन से उनका सम्मान और गौरव बढ़ा है। यूनिसेफ के सर्वे में यह बात उभरकर सामने आई है कि अब करीब 93 प्रतिशत महिलाएं मानती हैं कि उन्हें सम्मान मिला है और वे सुरक्षित महसूस करती हैं। हाल ही में एक शोध में पाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के शुरू होने के बाद नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है। शोध के निष्कर्ष में बताया गया है कि भारत में सन 2014 के बाद से हर साल 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं की जान बच रही है।

भारत में स्वच्छ भारत मिशन को शुरू हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। इस दौरान चरणबद्ध तरीके से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए गए स्वच्छता अभियान के सार्थक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इस अभियान से बच्चे, युवा, जवान और बुजुर्ग सभी जुड़े और यह देखते ही देखते जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। गांव-गांव और शहर- शहर में स्वच्छता को लेकर होड़ सी लग गई और इसके परिणाम स्वरूप गांव, जिला और प्रदेश सहित समूचे भारत में स्वच्छता की बयार बहने लगी। पूरे भारत में आम जनता की सक्रिय भागीदारी से खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ घोषित कर दिया गया। करीब 10 साल पहले स्वच्छता को लेकर हमारी मानसिकता पर जो गर्द जमी हुई थी, वह अब पूरी तरह साफ हो गई है। हमारी नजरें अब स्वच्छता के बीच केवल गंदगी पर ही जाकर टिकती है। जब चारों ओर स्वच्छता का वातावरण बन रहा है तब कहीं जरा सी भी गंदगी रहती है, वहीं हमारी नजरें ठहर जाती हैं। यह स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है।

स्वच्छता को लेकर प्रशासन के साथ आम नागरिकों में भी जुनून सवार है तभी तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत में सबसे स्वच्छ शहर का तमगा लेकर 7 सालों से शीर्ष पर बना हुआ है। इसमें आम नागरिकों और स्वयं सेवी संगठनों का भी सहयोग अतुलनीय है। इंदौर को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी स्वछतम शहर के रूप में मान्यता मिली हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अन्य शहर भी इंदौर से स्वच्छता के विभिन्न मापदंडों पर बराबर आने या इससे आगे निकलने की होड़ में शामिल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगे हैं। चूंकि स्वच्छता एक सतत प्रक्रिया है और निरंतर स्वच्छता को लेकर सजग रहकर इसके विभिन्न मापदंडों के स्तर को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब स्वच्छता धीरे – धीरे आम नागरिकों की आदत में शामिल होने लगा है। इसी का परिणाम है कि आज स्वच्छता के मापदण्डों पर भारत की छवि एक स्वच्छ राष्ट्र के रूप में बन रही है।

भारत में सन 2014 से पहले निर्मल भारत अभियान चलाया जा रहा था जिसमें केवल शौचालय बनाना ही एकमात्र लक्ष्य था लेकिन राशि इतनी कम (मात्र 4600 रूपये) थी कि इससे किसी तरह शौचालय ही बना पाते थे। यह कार्यक्रम औपचारिकता मात्र बन कर रह गया था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, शौचालय बनवाने के लिये राशि को बढ़ाकर 12,000 रूपये कर दिया जो शौचालय बनवाने के लिये पर्याप्त कही जा सकती है। शौचालयों के निर्माण के साथ पेयजल, स्वच्छता, पॉलिथीन मुक्त शहर - गांव आदि को भी इस अभियान में शामिल कर व्यापकता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों में शौचालय बनाना अनिवार्य कर दिया जिससे स्वच्छता अभियान को नया आयाम मिला और गरीबों विशेषकर महिलाओं को सम्मान। इसका परिणाम यह हुआ कि सन 2014 में जहां देश में शौचालयों का प्रतिशत करीब 40 था, जो अब बढ़कर करीब 97 प्रतिशत हो गया है। देश में 11.6 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाए। आज की तारीख में भारत के 50ऱ गांव ओडीएफ प्लस मॉडल हो चुके हैं। भारत करीब – करीब खुले में शौच से मुक्त यानी ओ.डी.एफ. के आसपास पहुंच चुका।

स्वच्छ भारत मिशन में पेयजल उपलब्ध कराना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश के करीब 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 13.76 करोड़ यानी 71.51 प्रतिशत परिवारों के घरों में नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है।

शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के साथ घर से निकलने वाले सूखे, गीले, जैव अपशिष्ट और इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक अपशिष्ट के व्यवस्था शुरू करने से शहरी स्वच्छता में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। घर से निकलने वाले सभी तरह के कचरे को घर से ले जाने के लिए सभी नगरीय क्षेत्रों में माकूल व्यवस्था की गई है। अनेक शहरों में गीले कचरे से जैविक खाद और बायोगैस बनाई जा रही है। उज्जैन के महाकाल सहित देश के अनेक धार्मिक स्थलों में फूल, पत्तियां से अब जैविक खाद बनाने के अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। इससे धार्मिक स्थलों में स्वच्छता का वातावरण निर्मित हो रहा है, कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और धार्मिक ट्रस्टों को आमदनी भी होने लगी है। देश में रिसायकल नहीं हो सकने वाली पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वच्छता के लिये तीन आर यानि रिडयूस, रियूज और रिसायकल अर्थात आवश्यकता कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रीकरण पर बल दिया गया है। इस प्रयास से आम नागरिकों के व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एक बार ही उपयोग (सिंगल यूज) में आने वाले प्लास्टिक / पोलिथीन से बने गिलास, प्लेट्स आदि का विवाह, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में रोक लगाने के लिये प्रभावी कदम उठाए गये हैं। अनेक नगरीय निकाओं और ग्राम पंचायतों ने बर्तन बैंक बनाकर पोलिथीन मुक्त शहर / ग्राम बनाने की दिशा में अनुकरणीय पहल की है।

भारत में इस समय चलाया जा रहा स्वच्छता ही सेवा - 2024 एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है जो स्वच्छ और स्वस्थ भारत के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। इस अभियान की विषयवस्तु स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता है। यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक दशक के परिवर्तनकारी कार्यों पर आधारित है, जिसने 2014 में अपनी शुरूआत के बाद से भारत के स्वच्छता परिदृश्य को मौलिक रूप से नया आयाम प्रदान किया है। पिछले दस वर्षों में स्वच्छता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता का वातावरण निर्मित हो गया है। अब भारत की छवि स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत के रूप में भी बन रही है। स्वच्छता को बनाये रखना सबसे बड़ी चुनौती है लेकिन यह असम्भव भी नहीं है। (लेखक- मधुकर पवार / ईएमएस)(भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी)

शब्द पहेली - 8138

बाएँ से दाएँ

1.कंठ,गला-3
3.पक्षियों का शौर-4
5.शारीरिक ऊँचाई-2
6.पाचन शक्ति-3
7.मां की माता-2
8.प्यार,प्रेम(अंग्रेजी-2)
10.रचना करने वाला-5
12.शोरबा,तरी-3
15.खाद्य सामग्री-3
17.दोनों हाथों को पीटना-5
20.भाग्य(अंग्रेजी-2)
22.कदली,एक फल-2
23.उपासना,शीश झुकाना-3
24.घ्राणेन्द्रिय,नासिका-2
25.तहखाना-4
26.दया-3

ऊपर से नीचे

1.मर्यादा,सीमा-2
2.कहानी लिखने वाला-5
3.अचरज भरा कार्य-3
4.वर,इच्छित वस्तु देना-4
5.जलजला-3
7.मां के पिता-2
9.चिकनाई-2
11.हशीश,एक प्रकार का मादक पदार्थ-3
13.बोलने का तरीका-3
14.तमीजवाला-5
15.परंपरा,रिवाज-4
16.राजनीतिक पार्टी-2
18.आफत,मुसीबत-2
19.नाट्य,कथा मंचन-3
21.कमी-3
24.संबोधन-2

शब्द पहेली - 8137 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

प्रसिद्ध कृष्णा और तनुश कोटियन की शानदार गेंदबाजी से इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी जीती

अनंतपुर (ईएमएस)। प्रसिद्ध कृष्णा और तनुश कोटियन की शानदार गेंदबाजी से इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। इस मैच में कृष्णा और तनुश ने तीन-तीन विकेट लिए जिससे उनकी टीम इंडिया ए ने इंडिया सी को 132 रनों से हरा दिया। इस प्रकार इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अंतिम दिन तक तीन टीमें खिताबी दौड़ में थीं पर सबसे अधिक 12 अंक होने के कारण इंडिया एक को जीत मिली। वीं इंडिया बी इंडिया डी से हार गई, जिससे इंडिया ए और सी के लिए मुकाबला हुआ। कप्तान मयंक अग्रवाल ने सुबह के सत्र में जल्दी पारी घोषित कर दी, जिससे उनके गेंदबाजों को विकेट लेने का पूरा समय मिल सके और उनकी ये रणनीति सफल रही।

वहीं इंडिया सी की टीम जीत के लिए मिले 350 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए लड़खड़ा गयी। उसकी शुरुआती बल्लेबाज पेवेलियन लौट गये। कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन ने दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी की पर इनके आउट होने के बाद पारी बिखर गयी।

इंडिया सी की ओर से सुदर्शन ने नाबाद 111 रन बनाये पर उन्य खिलाड़ियों का साथ उनको नहीं मिला। छह बल्लेबाज दो अंकों तक भी नहीं पहुंच पाये। कोटियन और कृष्णा की गेंदों का जबाव विरोधी टीम के बल्लेबाजों के पास नहीं था। इंडिया सी ने खेल को ड्रॉ पर समाप्त करने का भी प्रयास किया पर सफल नहीं हुई जिससे ट्रॉफी उसके हाथों से निकल गयी।

पूरन की आक्रामक पारी से त्रिनिदाद ने सेंट किट्स को 7 विकेट से हराया

जमैका (ईएमएस)। निकलस पूरन की आक्रामक पारी से त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रिआट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने 194 रनों के लक्ष्य को 1.3 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। इस मैच में कप्तान आंद्रे फ्लेचर 93 और काइल मेयर्स के 60 रनों की सहायता से सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रिआट्स ने 4 विकेट पर 193 रन बनाए। इन दोनों ने 5.1 ओवर में ही 43 रन बना डाले। केसी कार्टी के आउट होने के बाद जेसन रॉय और निकलस पूरन ने विरोधी टीम के गेंदबाजों को जमकर पीटा। पूरन ने 43 गेंद पर 7 छक्के और 6 चौके लगाकर 93 रन बनाए। वहीं जेसन रॉय ने 34 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की सहायता से 64 रन बनाए। पूरन और रॉय कुल 11 छक्के लगाए। वहीं सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रिआट्स के गेंदबाज एनरिक नॉर्किया ने 47 और जेरमियाह लुईस दोनो ने भी इतने ही रन लुटा दिये। जोश क्लार्कसन ने 1.3 ओवर में ही 28 रन दे दिए.

श्रीलंका ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 63 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की

गॉल(ईएमएस)। श्रीलंका ने यहां पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में मेहमान टीम न्यूजीलैंड को 63 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। यहां न्यूजीलैंड की टीम अंतिम दिन जीत के लिए मिले 275 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 211 रनों पर ही आउट हो गयी। इस मैच में कीवी बल्लेबाजी रचिन रवींद्र ने 92 रनों की शानदार पारी खेली पर वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाये। इस मैच में मेजबान श्रीलंकाई टीम शुरु से ही हावी रही। उसने अपनी पहली पारी में 305 रन बनाए थे पर न्यूजीलैंड ने 340 रन बनाकर 35 रनों की छोटी सी बढ़त हासिल की। वहीं मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 309 रन बनाकर मेहमान टीम को जीत के लिए 275 रनों का लक्ष्य दिया।

टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही सीरीज में मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी में कमिंदु मेंडिस की शतकीय पारी और कुसल मेंडिस के अर्धशतक से 305 रन बनाये थे। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से टॉम लेथम, केन विलियमसन और डेरेल मिचेल के अर्धशतक से टीम ने 340 रन बनाये।

दूसरी पारी में श्रीलंका ने दिमुथ करुणारत्ने, दिनेश चांदीमल और एंजेलो मैथ्यूज की अर्धशतकीय पारी के दम पर 309 रन बनाये। करुणारत्ने ने सबसे ज्यादा 83 रन बनाए जबकि चांदीमल ने 61 जबकि मैथ्यूज ने 50 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका के खिलाफ 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी असफल रही। उसके सात बल्लेबाज 10 रनों के अंदर ही आउट हो गये। केवल रचिन रवींद्र ने ही 92 रनों की पारी खेली।

जूनियर फुटबॉल और एमएमए में भी भारतीय खिलाड़ियों ने हासिल की जीत

नई दिल्ली ईएएमएस)। भारतीय टीम ने हाल में क्रिकेट के अलावा भी दो अन्य खेलों में अहम जीत हासिल की है पर हैरानी की बात है कि उसपर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में मिली 280 रनों की जीत के बाद क्रिकेटरों की तो खूब बातें हुईं पर फुटबॉल और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में मिली रिकार्ड जीत पर किसी का भी ध्यान इन खिलाड़ियों की ओर नहीं गया। क्रिकेट के अलावा भारतीय जूनियर फुटबॉल टीम ने भूटान में आयोजित सैफ अंडर-17 चैम्पियनशिप में जीत दर्ज की है। इसमें भारतीय टीम ने ग्रुप ए में बांग्लादेश को 1-0 से पराजित किया। इसमें भारतीय टीम की ओर से डिफेंडर सुमित शर्मा ने अंतिम क्षणों में सिर से गोल दागकर टीम को जीत दिलायी। इस जीत से भारतीय टीम को तीन टीमों के ग्रुप में तीन अंक मिले हैं। वहीं भारत के संग्राम सिंह ने भी जॉर्जिया (अमेरिका) में हुई इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप के मिश्रित मार्शल आर्ट (एमएमए) में भारत को पहली जीत दिलायी। संग्राम ने पाकिस्तान के अली रजा निसार को केवल 90 सेकंड में हराया। यह 93 किग्रा वर्ग में किसी पहलवान की सबसे कम समय में जीत का भारतीय रिकॉर्ड है। यह भी पहली बार हुआ है कि एमएमए में भारत के किसी पुरुष रेसलर ने अपना पहला ही मुकाबला जीता है।

टैट की अंतिम एकादश में सचिन , विराट शामिल

धोनी और मुरलीधरन में से किसी एक को ही जगह मिलेगी

सिडनी (ईएमएस)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैट ने अपनी पसंदीदा अंतिम एकादश चुनी है। टैट ने अपनी टीम में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर , और वीरेन्द्र सहवाग को शामिल किया है पर महेन्द्र सिंह धोनी , मुथैया मुरलीधरन में से किसी एक को ही इसमें जगह दी है। टैट ने स्पिनर के तौर पर इसमें ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न को चुना है, जबकि दूसरे स्पिनर के तौर पर मुरलीधरन को रखा है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर एडम गिलक्रिस्ट को रखा है पर महेन्द्र सिंह धोनी को विकल्प के तौर पर शामिल किया है। टैट ने सलामी बैटर के तौर पर गिलक्रिस्ट के साथ सहवाग को शामिल किया है। तीसरे नंबर के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को चुना है। वहीं चौथे नंबर पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। पांचवें नंबर पर उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा को रखा है जबकि छठे नंबर पर विराट कोहली को।

इसके बाद वॉर्न और तीन तेज गेंदबाज शामिल हैं। जिसमें वसीम अकरम, ग्लेन मैकग्रा और शोएब अख्तर को रखा है। वहीं 11वें नंबर के लिए उन्होंने धोनी या मुरलीधरन में से किसी को एक ही शामिल किया है। वहीं प्रशंसकों ने इस प्रकार की टीम बनाने पर टैट पर तंज कसा है और कहा है कि इस प्रकार की टीम बनाने का कोई मतलब नहीं है।

टैट की अंतिम ग्यारह एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया), वीरेंद्र सहवाग (भारत), रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया), सचिन तेंदुलकर (भारत), ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज), विराट कोहली (भारत), शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया), वसीम अकरम (पाकिस्तान), ग्लेन मैकग्रा (ऑस्ट्रेलिया), शोएब अख्तर (पाकिस्तान), मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) या एमएस धोनी (भारत) में से एक।

अश्विन ने वार्न के रिकार्ड की बराबरी की,दिग्गज खिलाड़ी के क्लब में जगह बनायी

चेन्नई (ईएमएस)। भारतीय टीम के अनुभवी स्पिनर आर अश्विन ने बांग्लादेश के खिलाफ हुए पहले टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी के साथ ही दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वार्न के एक रिकार्ड की भी बराबरी कर ली है। अश्विन ने इस मैच में शतक लगाने के साथ ही दूसरी पारी में छह विकेट लिए थे। इसी के साथ ही उन्होंने 37वीं बार पांच से अधिक विकेट लेने के वार्न के रिकार्ड की भी बराबरी कर ली है। अश्विन अब सबसे अधिक उम्र में पांच विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी गए हैं। इससे पहले पारी में शतक के साथ ही पांच विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में पूर्व दिग्गज इयान बॉथम, गैरी सोबर्स, मुश्ताक मोहम्मद, जैक्स कैलिस के अलावा वर्तमान में खेल रहे शाकिब अल हसन, रवींद्र जाडेजा हैं।

अश्विन कहा, 'मैं जब भी चेन्नई में आकर खेलता हूं तो यहां मुझे बेहद अच्छा लगता है। मैंने यहां काफी क्रिकेट देखा और खेला है। मैंने पहले दिन अच्छी बल्लेबाजी की और इसके बाद दूसरी पारी में विकेट लिए यह एक विशेष अनुभव है। मैं गेंदबाज होने के कारण उसी तरह सोचता हूं पर बल्लेबाजी के दौरान उसपर ध्यान रखता हूं।

शेयरबाजार रिकार्ड तेजी के साथ बंद,निफ्टी26 हजार के करीब पहुंचा, सेंसेक्स 384 अंक ऊपर आया

मुम्बई (ईएमएस)। मुम्बई शेयर बाजार सोमवार को भारी तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल एशियाई बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही विदेशी निवेश बढ़ने से आया है। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन 384.30 अंक करीब 0.45 फीसदी की बढ़त के साथ ही 84,928.61 के शीर्ष स्तर पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 148 अंक तकरीबन 0.57 फीसदी बढ़कर 25,939.05 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 25,847.35 और 25,956.00 के बीच कारोबार हुआ।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयर आज बढ़त पर बंद हुए। इसमें एमएंडएम, एसबीआईद्द, भारती एयरटेल, कोटक बैंक और एचयूएल जैसे शीर्ष पांच शेयर शामिल रहे। इसके अलावा, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, अदाणी पोर्ट्स, एनटीपसी, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले इंडिया, टाइटन, मारुति, रिलायंस, आईटीसी फाइनैंस, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स और बजाज फिनसर्व के शेयरों में भी तेजी आई।

दूसरी ओर सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 शेयर गिरावट पर बंद हुए। आईसी आईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक सेंसेक्स के सबसे अधिक नुकसान वाले पांच शेयर रहे। इसके अलावा, इंफोसिस, टीसीसएस, एलएंडटी, पावर ग्रिड, सन फार्मा और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर भी नीचे आये। बाजार जानकारों के अनुसार अमेरिकी फेडरल बैंक (फेड) द्वारा ब्याज दरों में की गई नीतिगत कटौती से से भी घरेलू बाजार ऊपर आया है।

इससे पहले आज सुबह बाजार के प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने सप्ताह के पहले कारोबारी ?दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर शुरुआत की। दुनियाभर के निवेशक इस बात पर नजर रख रहे हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बड़ी दर कटौती से आई तेजी कब तक बनी रहेगी। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 151 अंक बढ़कर 84,695 पर कारोबार करता नजर आया, जबकि निफ्टी 50 में 84 अंकों की बढ़त, यानी 0.33फीसदी की तेजी के साथ 25,875 पर कारोबार कर रहा था। वहीं एशिया-प्रशांत के बाजारों में सोमवार को धीमी शुरुआत देखी गई, क्योंकि क्षेत्र के निवेशक शुक्रवार को चीन और जापान द्वारा किए गए ब्याज दरों के फैसलों को समझने में लगे रहे। इससे पहले, यूएस फेड की तेज ब्याज दर कटौती ने पिछले हफ्ते बाजारों को मजबूती दी थी। सोमवार को जापान के बाजार एक सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी, एएसएक्स 200 इंडेक्स 0.43 फीसदी की गिरावट के साथ खुला। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.15 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 18,199 के स्तर पर दिखे, जो एचएसआई के पिछले बंद स्तर 18,258.57 से नीचे है।

आलू और प्याज की कीमतें बढ़ने की संभावना

नई ?दिल्ली (ईएमएस)। आलू-प्याज के उत्पादन को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिससे फिर से रसोई का खर्च बढ़ले की संभावना है। 2023-24 में भारत का बागवानी उत्पादन मामूली 0.65 फीसदी घटकर 353.19 मिलियन टन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जून में जारी 2023-24 के दूसरे एडवांस अनुमान में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 352.23 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था। प्रमुख क्षेत्रों में कम पैदावार के कारण प्याज और आलू का उत्पादन 242.44 लाख टन और 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है। अन्य सब्जियां जैसे बैंगन, रतालू और शिमला मिर्च का उत्पादन भी कम हो सकता है, जिससे इनकी कीमतों को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह खाद्य महंगाई को प्रभावित कर सकता है। भारत में अगस्त में खुदरा महंगाई 3.65 फीसदी पर पहुंच गई, जो जुलाई में 3.6 फीसदी थी। कुल सब्जियों का उत्पादन 205.80 लाख टन होने की उम्मीद है। अनुमानों से पता चला है कि टमाटर, पत्तागोभी, फूलगोभी, टैपिओका, लौकी, कद्दू, गाजर, खीरे, करेला, परवल और भिंडी के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की कीमत वृद्धि के कारण टमाटर का उत्पादन 4.38 फीसदी बढ़कर 21.32 मिलियन टन हो गया है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतें पिछले साल आसमान छूकर 250 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गईं, जिससे किसानों को ऊंची बाजार कीमतों का फायदा उठाने की उम्मीद में खेती बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। टमाटर के उत्पादन में वृद्धि से भोजन की लागत कम करने में मदद मिली है, शाकाहारी थाली में साल-दर-साल 8 फीसदी और मांसाहारी भोजन में 12 फीसदी की कमी आई है। फलों का उत्पादनआम, केले और अन्य फलों के कारण फलों का उत्पादन 2.29 फीसदी बढ़कर 112.73 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है।

सोना हुआ महंगा, चांदी के लुढ़के भाव

नई दिल्ली (ईएमएस)। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई लेकिन बाद में चांदी के भाव में गिरावट देखी जाने लगी। सोमवार को सोने के वायदा भाव 74,300 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 90,000 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में सोने के वायदा भाव में तेजी, चांदी के भाव में नरमी देखने को मिल रही है। सोने के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रेक्ट 165 रुपये की तेजी के साथ 74,205 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 240 रुपये की तेजी के साथ 74,280 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत भी तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रेक्ट 42 रुपये की तेजी के साथ 90,177 रुपये पर खुला। इस समय यह 61 रुपये की गिरावट के साथ 90,074 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। लेकिन बाद में भाव गिर गए। सोना पिछले बंद भाव पर ही खुला। कॉमेक्स पर सोना 2,646.20 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,646.20 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 7.90 डॉलर की तेजी के साथ 2,654.10 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 31.53 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 31.50 डॉलर था। इस समय यह 0.08 डॉलर की गिरावट के साथ 31.42 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

विमानन मनोविज्ञान के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का अभाव हैः नायडू

नई दिल्ली (ईएमएस)। नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने विमान परिचालन की सुरक्षा के लिए विमानन मनोविज्ञान क्षेत्र के साथ-साथ तनाव तथा थकान से निपटने के लिए मजबूत प्रणालियों की आवश्यकता पर सोमवार को जोर दिया।

उन्होंने पायलट सहित अन्य के लिए तनाव तथा थकान से निपटने के लिए मजबूत कार्यक्रमों की भी वकालत की। नायडू ने कहा कि विमानन मनोविज्ञान के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का अभाव है। उन्नत मनोवैज्ञानिक पहलुओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि मानवीय कारक भी विमान दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा विमान दुर्घटनाओं में मानवीय कारक पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में यह टिप्पणी की। नायडू ने कहा कि सुरक्षा उपायों को भारतीय विमानन क्षेत्र की तीव्र वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। उन्होंने लोगों को निरंतर कौशल प्रदान करने तथा उनका कौशल बढ़ाने का आह्वान किया।

एलआईसी की 100 रुपए की डेली एसआईपी शुरू करने की योजना

नई दिल्ली (ईएमएस)। एलआईसी म्युचुअल फंड की योजना छोटी रकम वाला सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) पेश करेगी। दरअसल कंपनी ने 100 रुपये की डेली एसआईपी शुरू करने की योजना बनाई है, जबकि फंड हाउस के लिए वर्तमान समय सीमा 300 रुपये है। कंपनी के एक व?रिष्ठ अ?धिकारी ने यह जानकारी दी। यह फैसला ऐसे समय आया है जब मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) छोटे एसआईपी की वकालत कर रहा है ताकि निवेशकों की भागीदारी ज्यादा हो। मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग फंड पर एनएफओ लॉन्च करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में अ?धिकारी ने कहा कि एएमसी रजिस्ट्रार केफिनटेक सर्विस के साथ काम कर रही है। एलआईसी म्युचुअल फंड की योजना रोजाना न्यूनतम एसआईपी रकम की मौजूदा सीमा को घटाकर 100 रुपये और मासिक एसआईपी के लिए घटाकर 200 रुपये करने की है। उन्होंने कहा कि इससे फंड हाउस को समाज के उन वर्गों तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जिन्हें शेयर बाजार में तेजी का फायदा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि फंड हाउस इस वित्त वर्ष के अंत तक अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को 35,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 65,000 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 1 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

भारतीय रियल एस्टेट बाजार में आवास की मांग मजबूतः क्रेडाई

सिडनी (ईएमएस)। भारतीय रियल एस्टेट बाजार में आवास की मांग मजबूत बनी हुई है और इसमें मंदी की कोई संभावना ?दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही मांग पूरा करने के लिए अधिक नई पेशकश की जरूरत है। रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष संगठन क्रेडाई के अनुसार किसी तिमाही में मकानों की बिक्री कम पेशकश की वजह से गिर सकती है, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद बढ़ी उपभोक्ता मांग बरकरार है। क्रेडाई 23-26 सितंबर को यहां अपना प्रमुख सम्मेलन क्रेडाई नैटकॉन आयोजित कर रहा है। इसमें 1,100 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। चालू तिमाही में बिक्री में अनुमानित गिरावट के बारे में पूछे जाने पर क्रेडाई के व?रिष्ठ अ?धिकारी ने कहा कि सितंबर तिमाही में नई पेशकश कम रही हैं। अ?धिकारी ने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा ?कि कोई इन्वेंट्री नहीं है। अच्छे डेवलपर की ओर से सही स्थानों तथा आकर्षक कीमतों पर आवासीय संपत्तियों की भारी मांग है।

अब तक 28 से ज्यादा कंपनियों ने भारतीय शेयर बाजार में किया प्रवेश

- सितंबर माह पिछले 14 सालों में आईपीओ के लिहाज से काफी व्यस्त

नई दिल्ली (ईएमएस)। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय शेयर बाजार में मजबूती बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बताया है कि सितंबर का महीना पिछले 14 सालों में आईपीओ के लिहाज से काफी व्यस्त रहने वाला है। अब तक, 28 से ज्यादा कंपनियों ने भारतीय शेयर बाजार में प्रवेश किया है, जबकि वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव जारी है।आरबीआई की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी इक्विटी मार्केट में छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की आईपीओ में बढ़ती रुचि देखी जा रही है, जिसमें घरेलू म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निवेशकों को आवंटित आईपीओ शेयरों में से करीब 54 फीसदी लिस्टिंग के एक सप्ताह के भीतर बिक गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले आठ महीनों में 60 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित धन जुटाने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों की बढ़ती संख्या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) की ओर बढ़ रही है। आरबीआई ने बताया कि वैश्विक संकेतों के बीच सेकेंडरी मार्केट में बेंचमार्क सूचकांक बढ़ा है और इसका दृष्टिकोण भी मजबूत बना हुआ है।

ग्लोबल फंड मई 2024 के बाद से लगातार पांचवें महीने में भारतीय लोन बाजार में भारी निवेश कर रहे हैं। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट कर्ज कम रहा है, क्योंकि जारीकर्ताओं ने अमेरिकी दरों में कटौती का इंतजार किया था। रिजर्व बैंक ने बताया कि बड़े जोखिम वाले पूंजी निवेशक बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं, और शुरुआती चरण के निवेश में सूक्ष्म उद्यम पूंजी कंपनियों और संस्थापक नेतृत्व वाले फंडों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि फिनटेक ऋणदाताओं ने निजी लोन में 52 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल की है और वे धन जुटाने तथा लोन स्त्रोतों में विविधता लाने के लिए निजी ऋण की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। इस प्रकार, भारतीय बाजार में निवेश के नए अवसरों के साथ-साथ चुनौतियों का सामना करते हुए बाजार में मजबूती का संकेत मिल रहा है।

भारत-बांग्लादेश दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा

पिच से स्पिनरों को सहायता मिलने की संभावना

मुम्बई (ईएमएस)। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच इसी माह 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले टेस्ट में जीत के साथ ही इस सीरीज में 1-0 से आगे है और उसका लक्ष्य इस मैच को भी जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम करना रहेगा। कानपुर क्रिकेट स्टेडियम की पिच पहले दिन से ही स्पिनरों की सहायक मानी जाती है। यहां की विकेट सूखी और धूल भरी होती है, जिससे स्पिनरों को अधिक टर्न मिलती है। इस विकेट में उछाल बहुत कम है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी।

भारतीय क्रिकेट ने इस स्टेडियम में अब तक 38 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी है। इसमें टेस्ट, एकदिवसीय और टी20 सभी शामिल हैं। सभी प्रारुपों को मिलाकर भारत ने यहां 17 मैच जीते हैं जबकि 18 में उसे हार मिली है। इसके अलावा 13 मैच बराबरी पर रहे हैं। इस स्टेडियम में सबसे ज्यादा स्कोर 676/7 रहा है। ये भारतीय टीम ने ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में बनाए थे.

भारत ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में कुल 23 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें 7 टेस्ट में भारतीय टीम को जीत मिली है। वहीं 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है जबकि 13 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की टीम अभी तक भारत से एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती है। दोनों के बीच कुल 14 टेस्ट मैच खेले गए हैं। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 12वीं बार टेस्ट में हराया है। वहीं एक ड्रॉ रहा जबकि एक अन्य का परिणाम नहीं निकला।

भारत डब्ल्यूटीसी फाइनल 2025 की रेस में सबसे आगे

मुम्बाई (ईएमएस)। भारत डब्ल्यूटीसी फाइनल 2025 की रेस में सबसे आगे है और उसके खिताबी मुकाबले में पहुंचने की पूरी उम्मीदें हैं। इसका कारण है कि अंक तालिका में भारतीय टीम शीर्ष पर बनी हुई है। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम पहला टेस्ट जीत गयी है अगर वह ये सीरीज जीत जाती है तो नंबर एक स्थान पर उसकी दावेदारी और पक्की हो जाएगी।

टीम इंडिया की डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स प्रतिशत 71.66 तक बढ़ गई है, जिसमें 10 टेस्ट में 86 अंक हैं। वह पहले से ही तालिका में शीर्ष पर मौजूद थी और अब उसने ऑस्ट्रेलिया से 9.16 प्रतिशत की बढ़त बना ली है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और इंग्लैंड सीरीज से पहले खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। टेस्ट मैचों की ये सीरीज जून से अगस्त के बीच खेली जाएगी। इसका पहला मैच 20 जून से होगा। वहीं अंतिम टेस्ट मैच 31 जुलाई से शुरू होगा। भारतीय टीम इंग्लैंड के पिछले दौरे में जीत के बेहद करीब पहुंचकर भी उसे हासिल नहीं कर पायी थी। ऐसे में इस बार उसका लक्ष्य जीतना रहेगा। भारत ने 2021 में इंग्लैंड दौरे पर 2-1 की बढ़त बना ली थी पर तब कोरोना संक्रमकण के चलते सीरीज बीच में रोक दी गयी थी। बाद में सीरीज का बाकी बचा एकमात्र मैच खेला गया, जिसे इंग्लैंड ने जीता। इस तरह सीरीज 2-2 से बराबर रही थी। इस बार सीरीज 4 अगस्त को खत्म होगी। सीरीज का पहला मैच लीड्स में खेला जाएगा. दूसरा मैच बर्मिंघम और तीसरा मैच लॉर्ड्स में खेला जाएगा। सीरीज का चौथा मैच मैनचेस्टर और पांचवां मैच 31 जुलाई से लंदन के ओवल में खेला जाएगा।

बांग्लादेश में सभी राजनीतिक बंदीरिहा होंगे,आदेश जारी

ढाका (ईएमएस)। बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस की लीडरशिप में बनी नई सरकार ने सत्ता संभालते ही हसीना सरकार के कई अहम फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है। ताजा फैसलों में नई सरकार ने उन सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई का आदेश दिया है, जिन्हें पूर्ववर्ती शेख हसीना सरकार के कार्यकाल के दौरान राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जेल में डाल दिया गया था।

गृह मंत्रालय ने सभी जिलों में एक विशेष समिति बनाने का निर्देश जारी किया है, जो इन मामलों की समीक्षा करेगी। इन समितियों के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर होंगे, जबकि मजिस्ट्रेट को सचिव बनाया गया है, और समिति में पुलिस अधीक्षक (एसपी) भी सदस्य होंगे। इन समितियों का प्रमुख कार्य राजनीतिक बंदियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा करना और मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव तैयार करना है, जिसे बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया पहले राजनीतिक नेताओं के मामलों से शुरू की जाएगी। जिला स्तरीय समितियां 31 दिसंबर तक मामले की जांच कर अपनी सिफारिशें सरकार को भेजेंगी। इन सिफारिशों के आधार पर, 45 दिनों के भीतर सभी राजनीतिक बंदियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस फैसले से देश में अराजकता फैलने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक बंदियों की रिहाई से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। हालांकि, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में मुकदमे वापस लिए जाएंगे।

केंद्र स्तर पर भी एक समिति बनाई गईहै,जिसमेंकानून, संसदीय कार्य मंत्रालय के सलाहकार और विभिन्न विभागों के सचिव शामिल हैं। यह समिति जिलों से प्राप्त सिफारिशों की समीक्षा करेगी और मामलों को वापस लेने के योग्य घोषित करेगी।सरकारकायह कदमदेशके राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलसकता है। बता दें कि पडोसी देश बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद उनकी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को बदला जा रहा है1

कर्ज में फंसा यूके, जीडीपी के मुकाबले 100 फीसदी से ज्यादा ले चुका है कर्ज

लंदन (ईएमएस)। ब्रिटेन अकेला विकसित देश नहीं है, जो भारी कर्ज के बोझ तले दबा है। जापान, जिसका कर्ज उसकी जीडीपी के 250 फीसदी के बराबर है, इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके अलावा, अमेरिका पर उसकी जीडीपी के मुकाबले 122 फीसदी कर्ज है।

ग्रीस, सिंगापुर और इटली भी ऐसे देशों में शामिल हैं जिन पर उनकी जीडीपी के मुकाबले 100 फीसदी से ज्यादा का कर्ज है। इस आर्थिक स्थिति ने विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ा दी है, खासकर तब जब दुनिया भर में महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के चलते देश पहले से ही वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाए, अन्यथा देश की आर्थिक स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है।

यूके ने अगस्त में 13.7 बिलियन पाउंड का कर्ज लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.3 बिलियन पाउंड अधिक है। यह कर्ज 1961 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। ब्रिटेन के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, कर्ज में यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि देश की आर्थिक स्थिति गंभीर है, साथ ही उपभोक्ता विश्वास भी गिरा है।ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी ने कहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने देश को जिस आर्थिक स्थिति में छोड़ा है, उसकी वजह से सरकार को कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। संभावित रूप से, ब्रिटेन की सरकार 30 अक्टूबर को बजट पेश करते समय टैक्स में वृद्धि और वेलफेयर बेनिफिट्स में कटौती कर सकती है। लेबर पार्टी के मुख्य सचिव डैरेन जोन्स ने कहा कि ये आंकड़े कंजर्वेटिव सरकार द्वारा छोड़ी गई चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाते हैं।

वेटिकन की तर्ज पर बनेगा एक अलग मुस्लिम देश, महिलाओं को भी पूरी आजादी का प्लान

तिराना (ईएमएस)। वेटिकन सिटी में ही पोप बैठते हैं और धर्म से जुड़े मामलों पर यहीं से राय देते हैं। इसी तर्ज पर एक मुस्लिम मौलवी ने भी एक देश बनाने की कोशिश की है, जहां से मुस्लिमों के मामले डील किए जाएंगे। यह देश अलबानिया की राजधानी तिराना में होगा। यह दुनिया का सबसे छोटा मुल्क होगा। इसका एरिया न्यूयॉर्क सिटी के 5 ब्लॉक जितना होगा। यहां शराब की मंजूरी होगी और महिलाओं को भी जो चाहें पहनने की आजादी होगी। उन पर लाइफस्टाइल से जुड़ी पाबंदियां नहीं रहेंगी।

मौलवी एडमंड ब्रहीमाज कहते हैं कि खुदा ने किसी भी चीज को लेकर रोक नहीं लगा रखी है। इसीलिए उसने हमें दिमाग दिया है कि हम तय करें कि क्या करना है। बाबा मोंडी के नाम से चर्चित एडमंड कहते हैं कि यह 27 एकड़ में बना देश होगा, जिसे अलबानिया एक अलग मुल्क के तौर पर विकसित करने को राजी है। इसका अपना प्रशासन होगा, सीमाएं तय होंगी और लोगों को पासपोर्ट भी जारी किए जाएंगे।

अलबानिया के प्रधानमंत्री ईदी रामा ने भी कहा है कि वह ऐसे एक देश के बारे में ऐलान करेंगे। यह देश इस्लाम की सूफी परंपरा से जुड़े बेक्टाशी ऑर्डर के नियमों को मानेगा। रामा ने कहा कि हमें इस खजाने की रक्षा करनी चाहिए, जिसका अर्थ धार्मिक सहिष्णुता से है और इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जो नया देश बनाने जा रहे हैं, वह पूर्वी तिराना में होगा। इसका साइज वेटिकन सिटी से भी एक चौथाई के बराबर होगा। इसमें लोगों पर पाबंदियां नहीं रहेंगी और उन्हें अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा। बाबा मोंडी का कहना है कि हम मानते हैं कि ईश्वर हम पर कोई बंदिश नहीं लगाता।

श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने दिसानायके....खुशी से उछल रहा चीन

बीजिंग (ईएमएस)। श्रीलंका में 56 साल के मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में एक वामपंथी नेता की जीत से चीन बेहद खुश हो रहा है। चीनी जानकार अभी से खुशी से उछल कर कह रहे हैं कि दिसानायके के सत्ता में आने से भारत पर श्रीलंका की निर्भरता कम होगी। उनका कहना है कि वामपंथी दिसानायके के सत्ता में आने से श्रीलंका के साथ चीन के संबंध और मजबूत होने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी तेजी आएगी।

साल 2022 में श्रीलंका के आर्थिक, राजनीतिक संकट के दौरान देश के अंदर से भी चीन के बीआरआई के खिलाफ आवाज उठी थीं। लेकिन अब जबकि श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ है और नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) के दिसानायके को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है, चीन को उम्मीद है कि दोनों देशों के संबंध मजबूत होने और बीआरआई प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम होगा।

दिसानायके की जीत पर चीन के सरकारी अखबार ने एक लेख छापा है जिसमें कई चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि दिसानायके के आने के बाद चीन-श्रीलंका संबंध और मजबूत होने वाले है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, श्रीलंका की नई सरकार के आने के बाद दोनों देशों के संबंधों के और बेहतर होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिसानायके की पार्टी की विचारधारा चीन के साथ मेल खाती है और चीन के साथ देश के संबंधों को महत्व देती है। रिपोर्ट में भारत का जिक्र करते हुए कहा गया कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भारत पर अपनी निर्भरता कम करने और चीन से अधिक जुड़ने का काम करेंगे।

लेख के अंत में लिखा, श्रीलंका की नई सरकार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के बीच अपनी अर्थव्यवस्था के विकास और अपने लोगों की आजीविका में सुधार को प्राथमिकता देगी. यह दिखाता है कि चीन-श्रीलंका संबंधों में बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि चीन श्रीलंका को बीआरआई में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में देखता है। चीन ने श्रीलंका में बंदरगाहों समेत कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है जिससे वहां के लोगों को फायदा हुआ है।

श्रीलंका की नई सरकार के पास भारत-चीन के साथ संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती है। नई सरकार को लेकर कहा जा रहा है कि यह चीन की तरफ झुकी हुई हो सकती है हालांकि, पार्टी ने आश्वासन दिया है कि पार्टी किसी भू-राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता में नहीं पड़ेगी। दिसानायके की एनपीपी पार्टी के प्रवक्ता बिमल रत्नायके ने कहा, श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होगा।

हिजबुल्ला के खात्में की तैयारी में इजराइल लोगों से तुरंत घर छोड़ने को कहा

तेलअवीव (ईएमएस)। इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ने लेबनान में लोगों को तुरंत अपने घरों और अन्य इमारतों को छोड़ने की चेतावनी दी है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह ने हथियार जमा करके रखा हुआ है।

आईडीएफ की ओर से घोषणा इजरायल द्वारा लेबनान में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे साफ होता है कि इजरायल अब हिजबुल्ला के खिलाफ सीधी लड़ाई में उतरने के मूड में है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि हम लेबनान के गांवों के नागरिकों को सलाह देते हैं कि वे अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत खतरे से दूर चले जाएं।

हिज्बुल्ला ने इजराइल के हालिया हमले में अपने एक शीर्ष कमांडर और कई लड़ाकों के मारे जाने के बाद बदले की कार्रवाई के तहत इजराइल के उत्तरी क्षेत्र को निशाना बनाकर 100 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे थे। हमलों और जवाबी हमलों के कारण व्यापक युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है जबकि इजराइल की गाजा में फलस्तीनी हमास के खिलाफ लड़ाई जारी है और वह सात अक्टूबर के हमले में बंधक बनाए गए कई बंधकों की वापसी की कोशिश कर रहा है।

मीडिया के अनुसार, अरबी में लिखे संदेश में कहा गया है कि अगर आप ऐसी इमारत में हैं जहां हिज्बुल्ला ने हथियार रखे हैं तब अगली सूचना तक उस गांव को छोड़कर चले जाइए। अभी यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि इजराइल के आदेश से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि सीमा के दोनों ओर के समुदाय लगभग हर दिन होने वाली गोलीबारी के कारण क्षेत्र को खाली कर चुके हैं। इजराइल ने हिज्बुल्ला पर दक्षिण में पूरे समुदायों को आतंकवादी ठिकानों में बदलने का आरोप लगाया है, जहां छिपे हुए रॉकेट लांचर और अन्य बुनियादी ढांचे हैं।

चीन में शादी से ज्यादा हो रहे हैं, तलाक

6 माह में हुए 13 लाख तलाक, बना विश्व रिकॉर्ड

बीजिंग (ईएमएस)। चीन सरकार ने तलाक की दर कम करने के लिए 2021 में एक कानून बनाया है। इस कानून के तहत 30 दिनों का समय आपसी समझौते के लिए रखा गया है। इस साल के प्रथम 6 माह में 13 लाख विवाहित जोड़ों ने तलाक लिया है। जो अपने आप मे वैश्विक स्तर का एक रिकॉर्ड है।

चीन की जनसंख्यकीय का अध्ययन करने ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने एक अनुसंधान किया है। उसके अनुसार चीन में बढ़ती महंगाई, काम का अत्यधिक दबाव होने से तलाक की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। चीन के दंपति अपनी निजी स्वतंत्रता और करियर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यह भी तलाक का सबसे बड़ा कारण है। चीन की जनसंख्या निरंतर कम होती जा रही है। इसको लेकर चीन की चिंता बढ़ी हुई है। चीन मे अब जितनी शादियां हो रही हैं। उससे ज्यादा तलाक हो रहे हैं। तलाक के बाद दंपति अपनी युगल फोटो नष्ट करने के लिए पेशेवर लोगों की सहायता ले रहे हैं। चीन में यह नया कारोबार शुरू हो गया है। जिसमें युगल फोटो को नष्ट करने का ठेका पेशेवरों को दिया जा रहा है।

खौफजदा ईरान...... सैनिकों से कहा संचार यंत्र का इस्तेमाल न करें

तेहरान (ईएमएस)। हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हुए इजरायली पेजर और वॉकी-टॉकी ब्लास्ट के बाद ईरान खौफजदा है। ईरानी सेना यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) ने अपने सभी सदस्यों को किसी भी तरह के संचार यंत्र का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है।

इतना ही नहीं खौफ से डरे ईरान ने आईआरजीसी के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच शुरू करा दी है। ताकि उनके यहां इस तरह का हमला न हो सके। इसकी जानकारी ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने मीडिया को दी। बताया गया हैं कि ज्यादातर डिवासेस ईरान में ही घरों में बनाए गए हैं। या फिर रूस और चीन से आयात किए गए हैं। आईआरजीसी के सभी जवानों के पास जितने भी गैजेट्स हैं, उन्हें जमा कराकर उनकी बारीकी से जांच की जा रही है।

भारत अब नई व्यवस्थाएं बनाता है और नेतृत्व करता हैः पीएम मोदी

न्यूयॉर्क(ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत में विकास अब एक जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा, हर भारतीय को भारत और उसकी उपलब्धियों पर भरोसा है। भारत आज अवसरों की भूमि है। देश अब अवसरों का इंतजार नहीं कर रहा है। यह अब अवसरों का सृजन कर रहा है। भारत अब नई व्यवस्थाएं बनाता है और नेतृत्व करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय अमेरिकियों से कहा, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने अपनी पुरानी सोच बदली। हमने अपना दृष्टिकोण बदला। हमने गरीबों को सशक्त बनाया। उन्होंने कहा कि यह नया मध्यम वर्ग ही है जो भारत के विकास को गति दे रहा है। मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए एआई का मतलब 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उनका मानना है कि एआई का मतलब 'अमेरिका-इंडिया भावना भी है।

न्यूयॉर्क में हजारों भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा, इस कठिन चुनाव प्रक्रिया, इस लंबी चुनाव व्यवस्था से गुजरने के बाद, भारत में (इस वर्ष) कुछ अभूतपूर्व हुआ। क्या हुआ...अबकी बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा, 60 साल में पहली बार भारत के लोगों ने ऐसा जनादेश दिया है जिसका बहुत महत्व है। अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान मुझे बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने हैं। हमें तीन गुना ताकत के साथ आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत आज अवसरों की भूमि है। मोदी ने देश और समुदाय को गौरवान्वित करने में भारतीय अमेरिकियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा, ''कल ही (अमेरिका के) राष्ट्रपति (जो) बाइडन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए। उनका स्नेह, उनकी गर्मजोशी, यह एक ऐसा क्षण था जिसने मेरे दिल को छू लिया। यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान की बात है। यह सम्मान आपके लिए है, आपकी उपलब्धियों के लिए है, यहां रहने वाले सैकड़ों-हजारों भारतीयों के लिए है।

एक सुर में बोले कई देश- लेबनान जल्दी छोड़ दें, कभी भी कुछ भी हो सकता है

वॉशिंगटन(ईएमएस)। इस वक्त इजरायल हिजबुल्लाह के आतंकियों के पीछे पड़ा हुआ है। उनके खात्मे के लिए लगातार इजरायली हमले बढ़ रहे हैं। अब हालात ये हैं कि लेबनान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस आशय की जानकारी कई देशों को मिली है। जिसके चलते उन्होंने अपने नागरिको के लिए अलर्ट जारी करते हुए हिदायत दी है कि जितना जल्दी हो सके लेबनान खाली कर दें। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन की सरकारों ने लेबनान में रह रहे अपने नागरिकों को सलाह दी है कि जितना जल्दी हो सके, देश छोड़ दें। अमेरिकी विदेश विभाग ने आग्रह किया है कि जब तक हवाई उड़ान उपलब्ध हैं, लेबनान खाली कर दें। कुछ दिन में सुरक्षा स्थिति बहुत खराब हो सकती है।

लेबनान पर हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष ने अमेरिका समेत कई देशों को चिंता में डाल दिया है। शनिवार रात अमेरिकी विदेश विभाग ने लेबनान में रह रहे अमेरिकियों से आग्रह किया कि वे जितना जल्दी हो सके देश छोड़ दें। अमेरिका ने इसके पीछे की वजह इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष बताया है। इसी प्रकार की सलाह फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा सहित कई देशों द्वारा भी दी गई है। नागरिकों को जारी एडवाइजरी में लेबनान न जाने की सलाह और लेबनान में अगर हैं, तो तुरंग स्थान खाली करने की एजवाइजरी जारी की गई है। चेतावनी दी गई है कि अगर देरी की तो आपातकालीन स्थिति में उनके दूतावास सहायता करने में सक्षम नहीं होंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले लेबनान पर इजरायल ने हवाई हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अहमद वाहबी समेत कई लोगों को मार डाला था। बेरूत में इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या 37 हो गई है।

हफ्ते भर पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध कैबिनेट में ऐलान किया था कि हमास के बाद अब हिजबुल्लाह से सीधी टक्कर का समय आ गया है। उन्होंने लेबनान से मिलती उत्तरी क्षेत्र में लोगों को फिर से बसाने और हिजबुल्लाह पर हमले तेज करने का ऐलान किया था। इसके बाद से हिजबुल्लाह पर लगातार हमले हो रहे हैं। पेजर और वॉकी-टॉकी अटैक में कई हिजबुल्लाह कमांडरों को इजरायल मौत की नींद सुला चुका है। उस हमले में 4 हजार से अधिक घायल भी हैं। शुक्रवार को बेरूत पर हुए हमले में मरने वालों की संख्या 37 हो गई। दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी इजरायल पर काउंटर अटैक कर रहा है। रविवार को इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में 100 से ज्यादा रॉकेट छोड़े। हालांकि इन हमलों से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ज्यादातर हमलों को शिन बेट और इजरायली वायु रक्षा प्रणाली द्वारा हवा में ही नष्ट कर दिया गया और बाकी निर्जन इलाकों में गिरे।

गुजरात के तीन शहरों को मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात, सड़कों के लिए 255 करोड़ रुपये आवंटित

गांधीनगर ,23 सितंबर

नगर निगमों की सड़केंः मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत राज्य के तीनों नगर निगमों को मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना से कुल 255.06 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं. सूरत नगर निगम मौजूदा सड़कों को चौड़ा करेगा, नई सड़कें बनाएगा, फुटपाथ और सीसी बनाएगा। मुख्यमंत्री ने सड़क एवं रोड कारपेट एवं री-कारपेट के विभिन्न 579 कार्यों के लिए 181.50 करोड़ रुपये आवंटित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.

राज्य सरकार द्वारा राज्य के महानगरों में इस योजना के तहत नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों की मरम्मत सहित कार्यों के लिए स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने इस संबंध में तीनों नगर निगमों के शहरी विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री ने सूरत नगर निगम के अलावा राजकोट नगर निगम को 12 विभिन्न शहरी सड़क कार्यों के लिए 60.78 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने गांधीनगर नगर निगम क्षेत्र में सड़क नवीनीकरण कार्यों के लिए 12.84 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा इस स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना में, मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना घटक में से, सूरत नगर निगम को रुपये आवंटित किए गए हैं। 740.85 करोड़, राजकोट नगर निगम 29 शहरी सड़क कार्यों के लिए रु. 168.94 करोड़ और गांधीनगर नगर निगम 7 कार्यों के लिए रु. 1529 शहरी सड़क कार्यों के लिए 57.68 करोड़ रुपये से 961.47 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

सुप्रीम कोर्ट से अहमदाबाद के निजी बस ऑपरेटरों को बड़ा झटका, प्रवेश संबंधी याचिका खारिज

अहमदाबाद (ईएमएस) सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद शहर में निजी बस ऑपरेटरों को बड़ा झटका देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को उचित ठहराते हुए उसे बरकरार रखा है। पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निजी ट्रैवल कंपनियों की लग्जरी बसें सुबह 8 बजे से रात 10 तक अहमदाबाद शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने निजी लग्जरी बसों को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक अहमदाबाद शहर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। निजी लक्जरी बसों के ऑपरेटरों की एकमात्र मांग यह थी कि 2004 में लक्जरी बसों को 18 मार्गों पर 24 घंटे चलने की अनुमति दी गई थी। इस मार्ग पर क्लीयरेंस बरकरार रखा जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने लग्जरी मैनेजरों की इस मांग को खारिज कर दिया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि यह ट्रैवल ऑपरेटरों की जिम्मेदारी है कि वे इन लोगों के लिए व्यवस्था करें जो लक्जरी बस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं। आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन और निजी परिवहन को कभी भी एक समान नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन और निजी परिवहन को बराबर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने वैकल्पिक मार्ग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। निजी ट्रैवल एजेंसियों से पेशेवर रोजगार के अधिकार और आरटीओ नियमों का हवाला देते हुए अधिसूचना को डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी गई थी।

हनीट्रैप के आरोपियों ने बिल्डर युवक से 7.25 करोड़ रुपये वसूले

अहमदाबाद,23 सितंबर

शहर के एक बड़े बिल्डर को उसकी गर्ल फ्रेंड के साथ क्लिप और फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार दो संदिग्धों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उसने पीड़ित युवक के एक खास दोस्त के साथ मिलकर पैसे जुटाए थे। जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन जुए में छह करोड़ रुपये हार गए हैं। इसके अलावा पीड़िता का वीडियो उपलब्ध कराने वाले युवक को 60 लाख रुपये देने की भी बात हो रही थी। बहरहाल, इस मामले को लेकर चल रहे ऑपरेशन को लेकर पूरे शहर के पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चा देखी जा रही है। अहमदाबाद के एक जाने-माने युवा बिल्डर ने कुछ दिन पहले आत्महत्या की कोशिश की थी। जिसके बाद परिवार ने जांच की तो पता चला कि कुछ लोग बिल्डर को ब्लैकमेल कर पैसे वसूल रहे थे और अब तक वह सवा सात करोड़ की रकम दे चुका है। तो पूरे मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई। जिसके आधार पर पुलिस ने गिरिश परिणी (निवासी वैकुंठ विहार सोसायटी, गैलेक्सी चार रास्ता, नरोडा) और अंकित पटेल नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी अंकित का खास दोस्त था पीड़ित बिल्डर और गिरीश से भी उसकी दोस्ती थी। जनवरी 2021 में गिरीश ने अंकित के साथ मिलकर एक लड़की भेजकर बिल्डर को फंसाने की साजिश रची। गिरीश ने वीडियो क्लिप और तस्वीरों के आधार पर बिल्डर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जिसमें डेढ़ करोड़ रुपये लिये गये थे। जिसमें पूर्व में तय हुए 60 लाख रुपये अंकित को दे दिये गये (जब लड़की को 50 लाख रुपये देकर विदेश भेजा गया। इसके अलावा उन्हें गोवा कैशियर से 18 लाख की रकम का नुकसान हुआ। 11 लाख का कर्ज चुकाने के लिए 20 लाख के सोने के आभूषण लिए थे.

डेढ़ करोड़ की वाजिब रकम लेने के बाद भी गिरीश ने बिल्डर को ब्लैकमेल किया और अलग-अलग समय में 5.75 करोड़ रुपये की रकम वसूली। इसमें से छह करोड़ रुपये तीन पत्ती के ऑनलाइन गेम में हार गए। उसने कुबेरनगर निवासी मनीष अरोरा से ऑनलाइन सट्टे के लिए आईडी ली थी। पुलिस जांच में गिरीश की तीन पत्ती आईडी से छह करोड़ के नुकसान का हिसाब मिला। इस प्रकार, 7.25 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उगाही की गई कोई भी रकम बरामद नहीं हो सकी. इस संबंध में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हनी ट्रैप के आरोपी गिरीश के खिलाफ सट्टेबाजी का मामला दर्ज किया है.

डॉ. तेजस दोशी 'स्वच्छ भारत मिशन-भारत सरकार' के लिए भावनगर के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए

गांधीनगर (ईएमएस) ''पिछले दशक के दौरान जंगलों की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है और सभी स्थानों पर प्लास्टिक की बोतल, थैलियां और कागज आदि नजर आ रहे हैं। किसी को तो इस कूड़े को साफ करने की शुरुआत करनी होगी! मैं स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से काफी प्रभावित हूं और जब इस धरती ने मुझे बनाया है, तो मुझे भी इस धरती को कुछ लौटाना चाहिए, इस विचार के साथ प्लास्टिक मुक्त भावनगर बनाने की मेरी यात्रा की शुरुआत हुई।'' यह कहना है भावनगर में पिछले 23 साल से जनरल फिजिशियन के रूप में सेवारत डॉ. तेजस दोशी का। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से देश भर में 'स्वच्छता ही सेवा अभियान' शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भीराज्यकेनागरिकोंमें 'स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता' की भावना उजागर करने के उद्देश्य से गुजरात भर में इस अभियान का शुभारंभ किया है। उधर, डॉ. तेजस दोशीगत एक दशक से 'स्वच्छता ही सेवा' के मंत्र फो आत्मसात कर भावनगर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का यज्ञ चला रहे हैं। डॉ. तेजस दोशी ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोचक प्रोजेक्ट चलाए हैं, जिनमें उन्हें शानदार सफलता मिली है। उनके स्वच्छता संबंधित प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए उन्हें वर्ष 2019 में भावनगर के लिए 'स्वच्छ भारत मिशन-भारत सरकार' का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।

2014 में पहली बार 'नो हॉन्किंग प्रोजेक्ट'

डॉ. तेजस दोशी ने वर्ष 2014 में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और युवाओं को बेवजह हॉर्न बजाने से रोकने के प्रयास के अंतर्गत 'नो हॉन्किंग प्रोजेक्ट' की पहल की। प्रारंभिक विचार यह था कि इस प्रोजेक्ट को 52 सप्ताह के लिए, 52 स्कूलों के 52 हजार बच्चों (हर स्कूल के 1000 बच्चे) को शामिल करते हुए शुरू किया जाए। बच्चे अपने स्कूल के निकट स्थित चौराहे पर गुजराती भाषा में ध्वनि प्रदूषण के बारे में जागरूकता से संबंधित बैनर लेकर एक घंटे तक खड़े रहते थे। किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं, केवल हाथों में बैनर लिए मौन खड़े रहते थे। इसके अलावा, ध्वनि प्रदूषण और हॉर्न नहीं बजाने से संबंधित पैम्फलेट भी छपवाए गए, और बच्चों को यह निर्देश दिया कि इस पैम्फलेट को मोड़कर चौराहे पर खड़े वाहन चालकों के हाथ में दें, ताकि लोग सहज कुतूहलवश उसे खोलकर पढ़ने के लिए प्रेरित हों। इस प्रोजेक्ट को जबरदस्त सफलता मिली ।

स्कूलों मासूम बच्चियों पर हो रहे अत्याचार के मामलों में सरकार कब कार्रवाई करेगीः कांग्रेस

अहमदाबाद (ईएमएस) दाहोद में मासूम बच्ची की हत्या और प्रदेश के शैक्षणिक परिसरों में बच्चियों पर हो रहे अत्याचार, जो पूरे शिक्षा जगत के लिए शर्म की बात है, पर भाजपा सरकार कब गंभीरता से कार्रवाई करेगी? यह सवाल उठाते हुए गुजरात प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक और प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि पूरे गुजरात राज्य में मासूम बच्चों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामले अभिभावकों के लिए भी चिंता का विषय हैं जब अपनी बेटियों को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेजने वाले माता-पिता के लिए ऐसी चिंताजनक घटनाएं होती हैं, ऐसे में शैक्षणिक परिसरों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए गंभीर कदम उठाने का समय आ गया है। पिछले 72 घंटों में दाहोद और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में हुई घटनाओं में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और पूरे मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई की जानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द सजा मिल सके। दाहोद के स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा किया गया कृत्य शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना हैं दाहोद के साथ-साथ बोटाद, अहमदाबाद, राजकोट के शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न की शिकायतें आने पर सवाल उठता है कि किस पर भरोसा किया जाए। गुजरात राज्य में स्कूल प्रबंधन समिति केवल कागजों पर है। शिक्षा विभाग से मांग है कि वह इस तरह की घटनाओं पर झूठ बोलने के बजाय गंभीर कदम उठायें जब कर्मयोगी जैसे कई प्रशिक्षणों पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं, तो यह कृत्य करने वाले नराधम शिक्षकों को किस तरह का प्रशिक्षण मिल रहा है?

गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिवराज सिंहकठवाडिया ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां सरकार बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं गुजरात के अभिभावक और लोग बेटी बचाओ की बात करने को मजबूर हैं दाहोद जिले के सिंहवाड में 6 साल की बच्ची की निर्मम हत्या ने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया हैं बेटी की हत्या करने वाला उसके स्कूल का प्रिंसिपल थी नराधम आचार्य गोविंद नट एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। गोविंद नाथ की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें से कुछचौंकाने वाली हैं। गोविंद नट संघगणवेश में और नराधम विश्व हिंदू परिषदके शिविर में हिस्सा लेते दिख रहा हैं इस शख्स की गुजरात के पूर्व मंत्री अर्जुनसिंह चौहान के साथ मुलाकात की फोटो हैं क्या संघ और विहिपऐसेलोगों का विरोध करेंगे? क्या भाजपा के नकली लोग दाहोद की बेटी के लिए कैंडल मार्च निकाल सकते हैं? राज्य में हुई घटनाओं ने शिक्षा क्षेत्र को शर्मसार कर दिया है और अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है कि आखिर वे किस पर भरोसा करें? नराधम आचार्य के नाम पर तीन से अधिक फेसबुक अकाउंट दिखाई देते हैं। उस खाते से 2015-16 के बाद की कोई भी तस्वीर दिखाई नहीं देती है। क्या कुछ भाजपा नेताओं की तस्वीरें होंगी? जिनके हटाए जाने की आशंका है। चिंता है कि राजनीतिक प्रभाव रखने वाले नराधम आचार्य को बचाने की कोई निरर्थक कोशिश होर्गी

अहमदाबाद के इन उद्यानों में प्रवेश के लिए नागरिकों को देना होगा शुल्क

अहमदाबाद (ईएमएस) अब तक आप उद्यानों ने मुफ्त में घूमने चले जाते थे, लेकिन अब गार्डन में प्रवेश के लिए फीस देनी होर्गी दरअसल अहमदाबाद नगर निगम में कमाई का एक और जरिया ढूंढ लिया हैं शहर के सिंधुभवन रोड स्थित उद्यानों में प्रवेश के लिए अब नागरिकों को शुल्क देना होगा। अगर आप सिंधुभवन रोड पर नवनिर्मित मोंटे कार्लो और गोटिला गार्डन जाना चाहते हैं तो आपको भुगतान करना होगा। शहर के इन दोनों उद्यानों में प्रवेश के लिए पर्यटकों को 10 रुपये का शुल्क देना पड़ेर्गा हालांकि इस गार्डन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है और इस दौरान कोई चार्ज नहीं देना होर्गा लेकिन अगर कोई सुबह 10 बजे से रात तक गार्डन में प्रवेश करता है, तो प्रति व्यक्ति 10 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। अगर कोई गार्डन में प्रवेश के लिए सालाना पास लेता है तो उसे 1 महीने की रियायत भी मिलेर्गी बता दें कि पहले इन दोनों उद्यानों में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता थी लेकिन अब से नागरिकों को इस उद्यान में प्रवेश लेने के लिए शुल्क देना होगा। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक सुबह और शाम को बड़ी संख्या में योग करने, व्यायाम करने और अपने समूह के साथ बगीचे में बैठने आते हैं। लोग अब ऑनलाइन माध्यम से भी शुल्क देकर उद्यान में प्रवेश ले सकेंगे। अभी तक गोटीला गार्डन में कोई सुविधाएं नहीं हैं और चार्ज वसूलने की व्यवस्था शुरू हो गई हैं

ज्योतिषी दंपत्ति ने अनुष्ठान के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपये ऐंठ लिए

अहमदाबाद,23 सितंबर, 2024

शहर के सैटेलाइट इलाके में रहने वाली एक महिला को पारिवारिक समस्या थी और जब उसने एक महिला ज्योतिषी से संपर्क किया, तो उसे ज्योतिषी द्वारा अनुष्ठान के नाम पर उसकी पत्नी से 20 लाख रुपये वसूलने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिसमें वह ज्योतिषी के नाम पर अलग-अलग मोबाइल नंबर और नाम बताकर धोखाधड़ी करता था। खासतौर पर उन महिलाओं को निशाना बनाया जाता था और ब्लैकमेल किया जाता था, जिनका अपने पति या ससुराल वालों के साथ अनबन होती थी और पैसे भी वसूले जाते थे। हालांकि इस मामले की जांच में आनंदनगर पुलिस को अब तक आरोपियों से कोई लिंक नहीं मिला है.

शहर के सैटेलाइट प्रेणतीर्थ इलाके में रहने वाली एक महिला अपने पति और सास से परेशान थी, इसलिए वह एक ज्योतिषी के विश्वास में आ गई और उक्त ज्योतिषी दंपति ने 20 लाख की रकम ऐंठ ली. इस मामले में जांच करने पर पता चला कि खुद को अमित त्रिवेदी बताने वाले शख्स का नाम अलकेश जोशी था और मनीषा नाम की महिला का नाम नीतू जोशी था. ज्योतिष दंपत्ति के नाम पर इस बंटी बबली ने न सिर्फ सेटेलाइट में रहने वाली महिला बल्कि अहमदाबाद के वासना, वडोदरा और सूरत समेत कई शहरों में कई लोगों को निशाना बनाया.

ज्योतिष दंपत्ति की कार्यप्रणाली ससुराल वालों द्वारा पीड़ित महिलाओं को निशाना बनाना था। जिसमें अनुष्ठान कराने के नाम पर लाखों रुपये लिए गए। जबकि कई मामलों में जो महिलाएं अपनी शादी से नाखुश थीं, उन्हें विश्वास में लेकर उन्हें कहीं और शादी करने के लिए कहा जाता था ताकि उनका भविष्य खराब न हो। जिसमें वह जिस युवक से पहले शादी तय कर चुकी थी उससे मिलने के बजाय फोन पर बात करती थी। इसके लिए अल्केश जोशी ने अपने दो भतीजों और अन्य दोस्तों की मदद ली और उन्हें शादी के लिए एक युवक के रूप में पेश किया। इसलिए भरोसा मिलने पर महिलाएं अधिक पैसे वसूलती थीं।

इस बंटी बबली ने अब तक 50 से ज्यादा महिलाओं को निशाना बनाकर लाखों रुपये ऐंठ लिए थे और इसके लिए वह अखबारों में विज्ञापन देते हुए अलग-अलग नाम औरमोबाइल नंबर भी देता था. इतना ही नहीं वह गुजरात के किस शहर का रहने वाला है? इसकी जानकारी उन्होंने पीड़िता को नहीं दी. अगर इस मामले की जांच आनंदनगर पुलिस गंभीरता से करेगी तो कई बड़े खुलासे होने की संभावना है.

आसरा केंद्र नडियाद द्वारा दिव्यांग साधना सहाय का वितरण

दिव्यांग साधन सहाय का वितरण भारतीय पशु अंग निर्माण निगम (एलिम्को) की अधिकृत बिक्री और मरम्मत एजेंसी आसरा केंद्र नडियाद द्वारा किया गया।

इस कार्यक्रम में 207 दिव्यांगजनों को कुल 118 बैटरी चलित ट्राइसाइकिल, 35 ट्राइसाइकिल, 126 व्हीलचेयर, 36 व्हील चेयर, 16 कान की मशीन एवं 63 लाख मूल्य के कुल 350 विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किये गये।

आसरा सेंटर निदेशक डॉ. चंद्र गोपाल के अनुसार, भारत सरकार ने विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में पहला नाडियाद मुकाम आसरा केंद्र शुरू किया है। इस केन्द्र में दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी आवश्यक सहायक उपकरण जैसे कृत्रिम हाथ, पैर, बैसाखी, वॉकर, छड़ी, तिपहिया साइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, चश्मा, कृत्रिम दांत आदि निःशुल्क एवं आसानी से उपलब्ध हैं।

इस सेंटर पर लगातार रजिस्ट्रेशन और टेस्टिंग चल रही है. 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगों को भी बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिलेगी। इस केंद्र के शुरू होने से किसी भी दिव्यांग व्यक्ति या वरिष्ठ नागरिक को आर्थिक सहायता पाने के लिए किसी अभियान या किसी संस्था या दानदाता का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस आसरा केंद्र की स्थापना स्थाई तौर पर की गई है ताकि कोई भी विकलांग या जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक किसी भी दिन कार्यालय समय के दौरान आसरा केंद्र में आकर अपना पंजीकरण करा सके और विशेषज्ञों द्वारा जांच के बाद आवश्यक उपकरण निःशुल्क प्राप्त कर सके। इसके बाद भी यदि किसी उपकरण की मरम्मत की आवश्यकता होगी तो मरम्मत की सुविधा भी इस आश्रय केंद्र पर उपलब्ध होगी.

अब तक इस केंद्र के 1000 से अधिक लाभार्थियों को कुल 2 करोड़ की राशि से लगभग 2000 उपकरण निःशुल्क वितरित किये जा चुके हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक शिविर आगामी 01 अक्टूबर को आयोजित किया जाना है।

इस कार्यक्रम में नडियाद विधायक श्री पंकजभाई देसाई, खेड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनीषभाई देसाई, आसरा सेंटर के निदेशक श्री चंद्र गोपाल, एलिम्को उज्जैन के प्रतिनिधि श्री चंदन चंद्रा और आसरा खेड़ा समन्वय ाक श्री राकेश चावड़ा उपस्थित थे।

वेदांता लिमिटेड के चेयरपर्सन श्री अनिल अग्रवाल की एक पोस्ट

पिछले तीन वर्षों में भारत में धातुओं की मांग में वृद्धि दरअसल खनिज उत्पादन की वृद्धि से कहीं अधिक रही है। तांबे की खपत में 22 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि कॉपर कन्सेंट्रेट का उत्पादन केवल 4 प्रतिशत बढ़ा। एल्युमीनियम के लिए खपत में 13 फीसदी की वृद्धि हुई लेकिन कच्चे माल बॉक्साइट में केवल 6 फीसदी की वृद्धि हुई। लौह मिश्र धातुओं के लिए खपत में 30 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि क्रोमाइट और संबंधित खनिजों का उत्पादन केवल 6 फीसदी ही बढ़ा है। यहां तक कि स्टील की 13 फीसदी की मांग भी लौह अयस्क की 11 फीसदी की वृद्धि से अधिक है।

इसका मतलब यह है कि भारत में इन खनिजों और धातुओं का आयात लगातार बढ़ रहा है। यहां तक कि तेल के लिए भी पिछले तीन वर्षों में औसत मांग 6 प्रतिशत की दर से बढ़ी है जबकि घरेलू उत्पादन वृद्धि में 1 प्रतिशत की गिरावट आई है। हमारे वार्षिक आयात बिल का 50 प्रतिशत, यानी 760 बिलियन डॉलर में से लगभग 380 बिलियन डॉलर प्राकृतिक संसाधनों के कारण है। अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, धातुओं और तेल की मांग और भी तेजी से बढ़ेगी।

भारत में तेल, खास तौर पर स्वीट क्रूड समेत सभी खनिजों में अपार भूगर्भीय क्षमता है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। अन्वेषण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर मंजूरी दी जानी चाहिए। हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ हिंदुस्तान कॉपर, भारत गोल्ड माइन, हट्टी गोल्ड माइंस जैसी परिसंपत्तियों के ब्राउनफील्ड विस्तार पर विचार करना चाहिए। इससे न केवल आयात में कमी आएगी बल्कि करोड़ों नौकरियां और अवसर पैदा होंगे, खास तौर पर कम कौशल वाले लोगों के लिए, जिससे गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हर देश जिसने प्रगति की है, उसने जमीन के नीचे के संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया है। हमें भी ऐसा करना चाहिए।

रीग्रीन-एक्सेल ईपीसी इंडिया लिमिटेड ने सेबी के समक्ष दाखिल किया डीआरएचपी

रीग्रीन-एक्सेल ईपीसी इंडिया लिमिटेड ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ठसेबीठ) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (ठडीआर एचपीठ) दाखिलकियाहै। रीग्रीन-एक्सेल ईपीसी को 31मार्च, 2024 तक भारत में इथेनॉलसंयंत्रों (डिस्टिलरी, चीनी और सह उत्पादन,जैव ईंधन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम और नवीकरणीय ऊर्जा)से संबन्धित अग्रणी कंपनियों में सबसे नई निर्माता कंपनी और आपूर्तिकर्ता के तौर पर पहचाना जाता है (स्त्रोतः एफएंडएस रिपोर्ट)।

कंपनी नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने, कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों का पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान, बैंक गारंटी प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्जिन मनी आवश्यकताओं को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव करती है।

आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

फिल्म संगीत ने हिंदी को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया हैः आनंद पंडित

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर पंडित चर्चा करते हैं कि किस तरह फ़िल्मी गीतों ने हिंदी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

अपने 60वें जन्मदिन पर, निर्माता आनंद पंडित ने फिल्म 'त्रिशूल' में सलीम-जावेद द्वारा लिखे गए एक संवाद का संदर्भ देते हुए एक भाषण दिया। उन्होंने यह भी चर्चा की कि कैसे हिंदी सिनेमा ने उन्हें मुंबई में अपने सपनों को जीवंत करने के लिए प्रेरित किया। आज एक सफल निर्माता के रूप में, पंडित यह मानते हैं कि सिनेमा ने दुनिया को हिंदी वाक्यांशों और गीतों से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वह कहते हैं, हिंदी फिल्म संगीत हमेशा से ही दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय रहा है। हाल ही में फ्रांस में संपन्न ओलंपिक मुकाबलों में, अमेरिका की कलात्मक तैराकी टीम ने ए आर रहमान के 'ताल' फिल्म के शीर्षक गीत पर अपना प्रदर्शन किया। 'पोलाइट सोसाइटी' नामक ब्रिटिश एक्शन कॉमेडी फिल्म ने 'देवदास' के गीत 'मार डाला' और आर डी बर्मन के गीत 'गुलाबी आंखें' को फिल्माया। स्पाइक ली की प्रशंसित 2006 थ्रिलर 'इनसाइड मैन' 'छैय्या छैय्या' के साथ शुरू हुई और मैं आपको ऐसे अनगिनत उदाहरण दे सकता हूं जब हमारे फिल्म संगीत ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया।ठ

केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के रु. 342 करोड़ का आईपीओ बुधवार, 25 सितंबर 2024 को खुलेगा

अंकित मूल्य पर 10 प्रति इक्विटी शेयर। 209 से रु. प्राइस बैंड 220 तय

अहमदाबाद, 23 सितंबर

केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड (ठकेआरएन हीट एक्सचेंजरठ या ठकंपनीठ) बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को अपने आईपीओ के संबंध में इक्विटी शेयरों की बोली/इश्यू खोलेगी। इक्विटी शेयरों के कुल निर्गम आकार (प्रत्येक 10 रुपये अंकित मूल्य) में 1,55,43,000 इक्विटी शेयरों तक का ताज़ा निर्गम (ठताज़ा निर्गमठ) शामिल है। ऊपरी मूल्य बैंड पर कुल निर्गम आकार रु. कम कीमत बैंड पर 341.95 करोड़ रुपये। 324.85 करोड़ (ठकुल निर्गम आकारठ)।

एंकर निवेशक बोली की तारीख मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 होगी। बोलियां/निर्गम बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को खुलेंगे और शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को बंद होंगे। बोली न्यूनतम 65 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 65 इक्विटी शेयरों के गुणकों (ठबोली विवरणठ) में लगाई जा सकती है।

प्रति इक्विटी शेयर इश्यू प्राइस बैंड रुपये है। 209 से रु. 220 (''प्राइस बैंड'') रखा गया है। कंपनी के इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त सकल आय का उपयोग (ए) राजस्थान के अलवर में नीमराना में एक नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए इक्विटी के रूप में हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी केआरएन एचवीएसी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के लिए किया जाएगा। ठप्रस्तावित परियोजनाठ) का मूल्य रु. 24,246.10 लाख (242.46 करोड़ रुपये) और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए (ठनिर्गम का उद्देश्यठ)।

इक्विटी शेयर 14 सितंबर, 2024 को जयपुर, राजस्थान में कंपनी रजिस्ट्रार के पास दायर किए गए कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (ठआरएचपीठ) के माध्यम से जारी किए जाने हैं और बीएसई लिमिटेड (ठबीएसईठ) पर सूचीबद्ध हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (ठएनएसईठ) पर सूचीबद्ध करने की योजना है

इसके अलावा, नेट इश्यू का न्यूनतम 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और नेट इश्यू का न्यूनतम 35 प्रतिशत सेबी आईसीडीआर नियमों के अनुसार, वैध बोलियों के अधीन, खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। निर्गम मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हुआ। गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को गैर-संस्थागत हिस्से के तहत आवंटन के लिए उपलब्ध इक्विटी शेयर निम्नलिखित के अधीन होंगेः

बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन ने सौर ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाया; उमरगांव यूनिट में 250 किलोवाट का अतिरिक्त रूफटॉप सोलर प्लान्ट स्थापित करेगी

23 सितंबर

भारत में एयरेटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट (एएसी) ब्लॉक, ब्रिक्स और पैनल के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक, बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने हाल ही में 250 किलो वाट के रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए ऑर्डर दिया है। कंपनी के उमरगांव (वापी) यूनिट में 450 किलोवाट की रुफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट पहले से ही स्थापित है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर उमरगांव यूनिट की कुल स्थापित क्षमता 700 किलोवाट से अधिक हो जाएगी।

बिगब्लॉक अपनी सभी विनिर्माण सुविधाओं में सोलर पावर प्लांट को लागू करके पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है। कंपनी ने पहले ही महाराष्ट्र के पालघर में अपने वाडा प्लांट में 625 किलोवाट की रुफटॉप सोलर प्रोजेक्ट शुरू कर दी है। अतिरिक्त 250 किलोवाट की स्थापना के

साथ, कंपनी की कुल स्थापित सौर क्षमता 1.3 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। ये पहल अपने कार्बन फूटप्रिंट्स को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के समर्पण को उजागर करती हैं।

बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष, श्री नारायण साबू ने कहा, ''हम अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में अपनी यात्रा में इस महत्वपूर्ण सिद्धि की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं। इन प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पन्न सौर ऊर्जा न केवल बिगब्लॉक की ऊर्जा खपत के एक महत्वपूर्ण हिस्से की भरपाई करेगी, बल्कि पर्याप्त परिचालन लागत बचत भी करेगी। यह वित्तीय लाभ कंपनी को अपनी स्थिरता पहलों में फिर से निवेश करने और हरित निर्माण क्षेत्र में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम करेगा। हम अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए अपने सभी प्लांट में रुफटॉप सोलर पावर सिस्टम लागू करने की इच्छा रखते हैं जो पर्यावरणीय प्रबंधन में हमारे समर्पण को और आगे बढाएगा। सौर ऊर्जा में निवेश करके, हम न केवल अपने पर्यावर णीय प्रभाव को कम कर रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की अपनी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित कररहे हैं।'' व्यावसायिक मोर्चे पर, कंपनी ने बिक्री में 19ऋ और शुद्ध लाभ में 80ऋ से अधिक के 5 साल के सीएजीआर की सूचना दी है।

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद

बिजली आपूर्ति व्यवस्था

ई-निविदा सं. ईएल/सी/एडीआई/टीआरडी/37/2024-25 (1) कार्य का नाम उसके स्थान सहित: पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल के अहमदाबाद-हिम्मतनगर गेज परिवर्तन कार्य के संबंध में GETCO 132 KV तलोद सबस्टेशन से WR ट्रेक्शन सबस्टेशन (TSS) तलोद तक 132 KV बिजली आपूर्ति व्यवस्था का प्रावधान । **(2) कार्य की अनुमानित लागत:** ₹15,12,49,250.58/- **(3) जमा कराने की बयाना राशी:** IREPS पोर्टल पर दर्शाए अनुसार, **(4) बिड जमा कराने एवं बिड खुलने की तिथि एवं समय:** IREPS पोर्टल पर दर्शाए अनुसार, **(5) निविदा शुल्क:** IREPS पोर्टल पर दर्शाए अनुसार, **(6) पूर्ण करने की समयावधि:** 12 माह **(7) वेबसाईट विवरण एवं नोटीस बोर्ड जहाँ निविदा का विवरण देख सकते है एवं कार्यालय का पता: वेबसाईट:** www.ireps.gov.in उप मुख्य विद्युत अभियंता (निर्माण) का कार्यालय एवं नोटीस बोर्ड, पश्चिम रेलवे, निर्माण भवन, असारवा, अहमदाबाद (गुजरात-382345) CPM-048

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे-अहमदाबाद

4 लेन रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए उप मुख्य अभियंता (निर्माण)-II, पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद निम्नानुसार कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित करते है : **ई-निविदा सूचना सं.** डेप्यु.सीई/सी/II/एडीआई-आरओबी-64-01 (दो पैकेट) **(1) कार्य का नाम उसके स्थान सहित:** अहमदाबाद मंडल के विरमगाम-महेसाणा अनुभाग पर विरमगाम-भंकोडा स्टेशनो के बीच कि.मी. 61/1-2 अंतर्गत LC सं. 64 के स्थान पर एप्रोचीज (छोर से छोर) सहित 4 लेन रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण । (दो पैकेट) **(2) कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 84,80,90,592.05 **(3) जमा कराने की बयाना राशी:** ₹ 4,39,00,500.00 **(4) निविदा प्रपत्र शुल्क:** शून्य **(5) कार्य की समापन अवधि:** 18 (अठरह) माह मॉनसुन सहित **(6) बीड जमा करने की तारीख एवं समय:** दिनांक: 10/10/2024 को 15:00 बजे । **(7) वेबसाईट विवरण नोटीस बोर्ड का स्थान जहाँ निविदा का संपूर्ण विवरण देख सकते है एवं कार्यालय का पता: वेबसाईट:** www.ireps.gov.in उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II, पश्चिम रेलवे, द्वितीय तल, 'C' विंग, निर्माण भवन, डीआरएम कार्यालय के पास, असारवा, अहमदाबाद-382345 CPM-047

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122 , 9327086467 R.N.I. 63177/ 95